राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 317 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार ,25 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

महामारी के दौर में अपना चरित्र दिखा रही कांग्रेस : तोमर

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ के कोरोना वैरिएंट को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोरोना महामारी के इस दौर में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। कमलनाथ जी जिस प्रकार के घटिया वक्तव्य दे रहे हैं, उससे कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट होता है।

बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा

पटना। बिहार में 16 से 25 मई तक के लिए लागू लॉकडाउन को और 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

नेपाली पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल

नई दिल्ली। नेपाल-भारत सीमा पर महोत्तारी जिले में नेपाल पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल हो गए हैं। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई। यह घटना उस समय हुई, जब भारतीय कारोबारियों ने मतिहानी नगर निगम में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के एक बनाई गई एक अस्थाई चौकी और हेल्प डेस्क को ध्वस्त कर दिया। सशस्त्र पुलिस बल का एक जवान और 8 भारतीय कारोबारी झड़प में घायल हो गए। मतिहानी सीमा चौकी के पुलिस निरीक्षक बलराम गौतम ने बताया कि रात 8 बजे 50-60 भारतीय नागरिकों ने सीमा पर तैनात जवानों पर पथराव किया।

कार्टून

टूलकिट मामले में छानबीन करने ट्विटर के दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम

नई दिल्ली। कोरोना को लेकर जारी कथित टूलकिट मामले में पुलिस की छानबीन तेज हो गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मसले पर पहले माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजने के बाद अब उसके दफ्तर पर पहुंचकर छानबीनी की है. आज शाम दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर के दिल्ली और हरियाणा स्थित दफ्तर पर पहुंची. दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली के लाडो सराय इलाके में स्थित ट्विटर दफ्तर पर पहुंचकर छानबीन की. टूलकिट मामले को लेकर ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट्स के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखे जाने को लेकर स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की. इसी मसले पर स्पेशल सेल ने ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.

इससे पहले आज दिन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी. बता दें कि कोरोना टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट शेयर किए थे. कई पोस्ट्स में टूलकिट को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस को शिकायत भी दी थी. इसके बाद ट्विटर ने ऐसे पोस्ट्स के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था, जिस पर बीजेपी नेताओं के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई थी.

केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर कहा था कि ट्विटर की इस हरकत से इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट के मध्यस्थ और तटस्थ रहने की भूमिका पर सवाल उठते हैं. केंद्र सरकार ने टूलकिट को देश में कोरोना रोकथाम की कोशिशों को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए कहा था कि जब तक इस मामले की जांच की जा रही है, ट्विटर पोस्ट्स के नीचे लगाए गए मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाए. सरकार ने ट्विटर को दोटूक कहा था कि ट्विटर ये तय नहीं करेगा, बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से पता चलेगा कि यह कंटेंट सही है या गलत. जब तक इस प्रकरण की जांच हो रही है, तब तक ट्विटर अपना फैसला नहीं दे.

गौरतलब है कि संबित पात्रा ने गत 18 मई को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान टूलकिट के बारे में पर्दाफाश किया था। उक्त मसले को लेकर ही उन्होंने ट्वीट भी किया था, ताकि इंटरनेट मीडिया के जरिये लोगों को सच्चाई का पता लग सके, लेकिन ट्विटर की तरफ से उनके उक्त ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया जिस पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सरकार ने ट्विटर को भेजे अपने संदेश में कहा है कि संबंधित पक्षों में से एक ने कानून प्रवर्तन एजेंसी के सामने टूलकिट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए शिकायत की है। इसकी जांच की जा रही है।

उधर, संबित पात्रा के आरोप पर गत दिनों यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शिवी चौहान ने उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि पात्रा कोरोना संक्रमण के बीच सांप्रदायिक तनाव फैलानेके लिए फर्जी कांग्रेस टूलकिट को प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस इस शिकायत पर भी जांच कर ही रही थी कि उसी दौरान ट्विटर ने हस्तक्षेप किया, जिसके लिए सेल को ट्विटर के महानिदेशक को नोटिस भेजना पड़ा।

सीबीआई का अगला निदेशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सीबीआई का अगला निदेशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर समिति की बैठक आयोजित की गयी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी समिति की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं और इस समिति को केंद्रीय जांच ब्यूरो का अगला निदेशक (डायरेक्टर) चुनना है। समिति को चार वरिष्ठतम बैचों (1984-87) के आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक को अगला सीबीआई प्रमुख चुनना है।करीब चार माह की देर के बाद यह बैठक आयोजित हुई है।

सीबीआई प्रमुख की दौड़ में मुख्य रूप से असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी और एनआईए के महानिदेशक वायसी मोदी, गुजरात कैडर के बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना और हरियाणा कैडर के आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी, केरल के डीजीपी लोकनाथ बेहरा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी अरुण कुमार और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी एसके जायसवाल भी दावेदारी में हैं। कमेटी कुल मिलाकर 1984-87 बैच के 100 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

कमेटी वरिष्ठता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधक केसों की जांच के अनुभव के आधार वरिष्ठतम बैचों के आईपीएम अधिकारियों में से सीबीआई डायरेक्टर का चयन करेगी। सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर चुना गया अफसर, पदभार ग्रहण करने के बाद कम से कम दो साल की अवधि तक इस जांच एजेंसी का कार्यभार संभालेगा। दो साल की अवधि पूरा करने के बाद आरके शुक्ला इस साल फरवरी में सीबीआई डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। सीबीआई के एडीशनल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा पूर्णकालिक नियुक्ति होने तक फिलहाल सीबीआई के प्रमुख का कार्य संभाल रहे हैं।

फंगस संक्रमण को रंग से पहचानना उचित नहीं, इम्यूनिटी में कमी है मुख्य वजहः स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली । देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस में एम्स के निदेशक डॉ.रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है। इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कम इम्यूनिटी वाले लोग म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस), कैंडिडा और एस्पोरोजेनस संक्रमण से संक्रमित होते हैं। ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है। इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइनस, राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है।

अलग-अलग रंगों से इसे पहचान देना गलत है। म्यूकोरमायकोसिस यानी ब्लैक फंगस की पहचान किसी रंग के साथ करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि इस फंगस संक्रमण को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या पीला फंगस कहना ठीक नहीं है। एक ही फंगस की पहचान अलग-अलग रंगों से करने से भ्रम पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं कि आक्सीजन सिलेंडर से फंगस संक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में बिना आक्सीजन सपोर्ट के रहने वाले मरीजों को भी फंगस संक्रमण हुआ है। ये संक्रमण यानी छुआछूत कोरोना की तरह नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई का ध्यान रखें। उबला पानी पिएं। नाक के अंदर दर्द-परेशानी, गले में दर्द, चेहरे पर संवेदना कम हो जाना, पेट में दर्द होना इसके लक्षण हैं। रंग के बजाय लक्षणों पर ध्यान दें। गुलेरिया ने कहा कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी के बाद लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम 4-12 हफ्ते तक रह सकते हैं। सांस में दिक्कत, बदन सीने में दर्द, खांसी, थकान, जोड़ों में दर्द, तनाव, अनिद्रा जैसी शिकायत रहती है। उनके लिए काउंसलिंग, रिबाबिलिटेशन और ट्रीटमेंट जरूरी है। योग भी बेहतरीन काम करता है।

डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। हमारे पास केवल यह दिखाने वाला डेटा है कि वायरस मनुष्यों से जानवरों में फैलता है जैसा कि पहली लहर के दौरान न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में देखा गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 2,22,000 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 40 दिन के बाद यह अब तक के सबसे कम मामले दर्ज़ किए गए हैं। ज़िला स्तर पर भी कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। 3 मई तक रिकवरी दर 81.7 फीसद थी अब यह बढ़कर 88.7 फीसद हो गई है।

पिछले 22 दिनों से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। 3 मई के समय देश में 17.13 फीसद सक्रिय मामलों की संख्या थी, अब यह घटकर 10.17 फीसद रह गई है।

अब येलो फंगस की दस्तक, ब्लैक और वाइट से भी ज्यादा खतरनाक

गाजियाबाद, (एजेंसी)। कोरोना महामारी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक और व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी। इस बीमारी से अब तक यूपी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस की इंट्री ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस के एक मरीज में पुष्टि की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि 45 वर्षीय जिस मरीज में येलो फंगस मिला है वह पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और इस समय डायबिटीज से भी पीड़ित है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस मरीज का इलाज करने के लिए ओटी में सफाई चल रही थी, इसी दौरान जांच में पता चला कि मरीज येलो फंगस से भी संक्रमित हो चुका है। हालांकि मरीज की हालत में पहले से सुधार है। गाजियाबाद के इएनटी स्पेशलिस्ट डॉ.बीपी त्यागी ने बताया कि रविवार को संजय नगर से मेरे पास एक मरीज आया था। एंडोस्कोपी टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस है। येलो फंगस रेप्टाइल्स में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि पहली बार मैंने इसे इंसानों में देखा है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस की पुष्टि ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी को म्यूकर स्पेक्टिक्स कहा जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह इस हद तक खतरनाक हो सकता है कि मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी यह येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता था। इतना ही नहीं यह जिस रेपटाइल को फंगस होता है वह जिंदा नहीं बचता, इसलिए इसे बेहद खतरनाक और जानलेवा माना जाता है।

कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिले मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल, कोर्ट ने कोविड-19 से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति की मांग वाली याचिका पर सरकार से सवाल किया है कि क्या कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए कोई एक समान पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र को नोटिस भेजकर 10 दिनों में जवाब मांगा है।

बता दें कि जनहित याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राज्य सरकारों को निर्देश दे कि मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में मौत की वजह कोरोना वायरस दर्ज किया जाए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र को कोविड-19 से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इसके लिए समान नीति अपनाई जाए। शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इन याचिकाओं में केंद्र और राज्यों को साल 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रु अनुग्रह राशि देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति नहीं होगी, जिसमें कहा गया हो कि मृत्यु का कारण कोविड था, तब तक मृतक के परिवार वाले किसी भी योजना के तहत, अगर ऐसी कोई है, मुआवजे का दावा नहीं कर पाएंगे। पीठ ने केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख तय की।

चक्रवात की राहत पर सियासी तूफान, ममता बोलीं- दूसरे राज्यों के मुकाबले कम मदद

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को मदद का जो वादा किया है, उसमें बंगाल के साथ भेदभाव किया गया है। ममता ने कहा कि गृहमंत्रालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए अडवांस में देने का वादा किया है, लेकिन बंगाल को केवल 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

ममता ने इसे भेदभाव बताते हुए राज्य में की गई तैयारियों का ब्योरा भी दिया है। 4000 साइक्लोन शेल्टर्स तैयार हैं, 10 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। 51 डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, 1000 इलेक्ट्रिसिटी और 400 मोबाइल नेटवर्क बहाली टीमें गठित की गई हैं। 20 जिले बहुत अधिक प्रभावित होंगे।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि चक्रवाती तूफान यास बंगाल की पूर्व-मध्य खाड़ी के ऊपर से आगे बढ़ रहा है और यह तेजी पकड़ने की प्रक्रिया में है। आईएमडी अधिकारी ने कहा कि चक्रवाती यास 16.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 89.6 डिग्री पूर्वी देशांत के पास बंगाल की पूर्व-मध्य खाड़ी में केंद्रित है। जो सोमवार सुबह साढे आठ बजे अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर से 620 किलामीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में ओडिशा के पारादीप से 530 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में, बालासोर के 630 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में और पश्चिम बंगाल के दीघा के 620 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि मौसमी दशाओं के अगले 12 घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने आशंका है और इसके बाद यह 26 मई की सुबह तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा, और तेज होगा तथा 26 मई की सुबह तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। इसी दिन दोपहर तक यह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और इसके पारादीप और सागर द्वीपों के बीच उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान है।

चक्रवाती तूफान यास से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने पयार्प्त इंतजाम किए हैं। नौसेना और वायु सेना नौसेना को बचाव टीमों के साथ स्टैंडबाय के तौर पर रखा गया है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पांच तटीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चक्रवात से उत्पन्न स्थिति और उससे संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की भी समीक्षा की है।

राज्यपाल को पद से हटाते ही जेल भेज देंगे : टीएमसी सांसद

कोलकाता, (एजेंसी)। नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस को लेकर गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गर्वनर को धमकी देकर कहा है, कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के गवर्नर पद से हटते ही उन्हें जेल भेज देगी। कल्याण ने कहा, हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते, इसकारण हमारी लोगों से अपील है कि वह गवर्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। कल्याण ने कहा कि चुनाव के दौरान और बाद में जहां-जहां पर हिंसा हुई है, वहां के लोग गवर्नर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएं।उन्होंने कहा कि गवर्नर जगदीप धनखड़ को उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा, जहां नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जिस तरह का माहौल देश में बन चुका है, उसके बाद साल 2024 के चुनाव में बीजेपी के कई नेता जेल के अंदर होने वाले है। भारत के लोग अब दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं।

टीएमसी सांसद की टिप्पणी पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देकर हैरानी जाहिर की। बता दें कि नारदा स्टिंग केस मामले को गवर्नर ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार के दो मंत्रियों सुब्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम समेत 4 नेताओं को अरेस्ट कर उन्हें जेल भेजा गया था।सीबीआई की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से टीएमसी के कई नेता गवर्नर जगदीप धनखड़ पर हमलावर हो गए हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि फिरहाद हाकिम को स्टिंग ऑपरेशन करने वाले से पांच लाख रुपये रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए देखा गया, जबकि मदन मित्रा और सुब्रत मुखर्जी को कैमरे पर पांच-पांच लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।शोभन चटर्जी को स्टिंग करने वाले से चार लाख रुपये लेते हुए देखा गया। सीबीआई के अनुसार आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को भी कैमरे पर पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया।

बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से इजरायल को छोड़कर शब्द को हटाया

ढाका, (एजेंसी)। बांग्लादेश के पासपोर्ट में बड़े बदलाव के बाद इजरायल के साथ संबंधों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर से इजरायल को छोड़कर शब्द को हटा दिया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर पहले एक शर्त होती थी कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। लेकिन अब बांग्लादेशी सरकार ने पासपोर्ट को पूरी दुनिया के लिए वैध बना दिया है।

इसके बावजूद बांग्लादेश ने इस स्पष्ट किया कि उसने इजरायल के संबंध में अपने पासपोर्ट के एक वाक्यांश को हटाया है, लेकिन यहूदी देश की यात्रा पर प्रतिबंध वाली उसकी दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। इजरायल ने बांग्लादेश के इस कदम का स्वागत कर ढाका से आह्वान किया है कि वह दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए तेल अवीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे।

इजरायल के विदेश मंत्रालय में उप महानिदेशक गिलाद कोहेन ने ट्वीट कर लिखा अच्छी खबर! बांग्लादेश ने इजराइल के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं बांग्लादेशी सरकार से आगे बढ़ने और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आह्वान करता हूं ताकि दोनों देशों के लोगों को लाभ मिले और समृद्धि हो सके।

हालांकि, कुछ ही घंटों के बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्री डॉ एके अब्दुल मोमीन ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला रहे हैं, कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब कतई ना निकले, कि इजराइल को लेकर बांग्लादेश के रुख में कोई बदलाव आया है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब भी बांग्लादेशी पासपोर्ट धारकों को इजरायल की यात्रा करने की इजाजत नहीं है। आठ दशकों के इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष में बांग्लादेश ने हमेशा से फिलीस्तीनियों का पुरजोर समर्थन किया है। इसने कभी इजरायल के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है और इसलिए दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं।

कोरोना की लहर को नहीं रोका गया तब हम खत्म हो जाएंगें: लोटे शेरिंग

थिंपू, (एजेंसी)। भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने देश में कोविड-19 के खतरे को देखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यदि अभी वायरस पर काबू नहीं हुआ हम खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री शेरिंग ने डेढ़ साल बाद भी बरकरार महामारी के खतरे की याद जनता को दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बदतर हालात को भूटान महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी तैयारियों के बावजूद इसकी गारंटी नहीं कि जो भारत झेल रहा है वहीं भूटान नहीं झेलने वाले है। उन्होंने कहा, दक्षिणी सीमा का खतरा अब पूर्व तक पहुंच गया है। यदि हम सावधान नहीं रहे, हमारे पड़ोसी की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोर्स-सीओवी-2 तेजी से म्यूटेशन कर रहा है और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश धीरे-धीरे सभी ओर से खतरे से घिरता जा रहा है। यदि पर्याप्त उपाय नहीं किए गए और लोगों ने रोकथाम के उपाय नहीं किए,तब वायरस को देश में घुसने में देर नहीं लगेगी। कोविड-19 के दो लहर के बाद देश में अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह आपदा खत्म हो गई। लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आशा की एक किरण है। प्रधानमंत्री ने कहा, यदि हम हालात को नियंत्रण में अभी नहीं कर सकें,तब सभी खत्म हो जाएंगे। इस बीच ट्रशिगैंग टाउन में 21 मई की रात 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया। योनफुला एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। भूटान में पहला कोरोना संक्रमण का मामला 6 मार्च 2020 को आया था।

मिनापोलिस में पुलिस के हाथों मारे गये अश्वेत जॉर्ज फ्लायड की मौत के एक साल पूरे होने पर एक रैली निकाली गयी।

इटली के पिडमेंट क्षेत्र में एक कार के हादसे का शिकार होने के बाद राहत कार्यों में लगे दल के सदस्य।

चीन में तलाक के मामले हुए 70फीसदी कम

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन में तलाक को लेकर बनाए गए कूल-ऑफ नियम का असर अब देखने को मिल रहा है। यह तलाक के मामलों में सत्तर फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में 296,000 तलाक के मामले पंजीकृत हुए थे, वहीं इसके मुकाबले पिछले साल की अंतिम तिमाही में 10 लाख 60 हजार तलाक के मामले पंजीकृत किए गए थे - यानी 72 फीसदी की गिरावट आई है, वहीं 2020 की पहली तिमाही में 612,000 मामले आए थे जिसकी तुलना में भी इस साल 52 फीसद की गिरावट देखने को मिली है।

कहा जा रहा है कि कूल ऑफ नियम के चलते आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है.दरअसल, चीन में 1 जनवरी 2021 से सिविल कोड लागू किया गया है जिसे मई में संसद से मंजूरी मिल गई थी। इस कानून को चीन में तलाक के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जोड़ा गया है इस नियम के तहत अब पति-पत्नी को तलाक की अर्जी देने के एक महीने तक कूल-ऑफ अवधि बितानी होगी, अगर इस दौरान दोनों में से किसी का भी मन बदलता है तो वो अपनी अर्जी वापस ले सकता या सकती है इससे पहले तलाक की अर्जी लगाते ही पति-पत्नी को तलाक मिल जाया करता था.ये कानून, चीन के कई इलाकों में पहले से ही लागू है, देश भर में इसे लागू किया जाने पर सरकार को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा इसे निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, और जबरन लोगों को ऐसे रिश्ते में बांधने की कोशिश बताई जा रही थी जिससे वो खुश नहीं है। लेकिन राज्य में कई लोगों ने इसे पारिवारिक मजबूती और सामाजिक स्थिरता के लिए बेहतर भी बताया है।ऑल चाइन वुमेन फेडरेशन के मुताबिक बीते सालों में चीन में तलाक के मामले बढ़े हैं जिसकी एक वजह महिलाओं की स्वायत्ता को बढ़ावा देने और दूसरी वजह तलाक को धब्बे के तौर पर न देखा जाना है इस तरह के तलाक के मामलों में 70 फीसद से ज्यादा में पहल करने वाली पत्नियां हैं इस चलन ने कई नीति निमार्ताओं को सचेत किया और नागरिक मामलों से जुड़े मंत्रालय के अधिकारी यांग जोंगताओ ने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शादी और प्रजनन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर शादी की दर में गिरावट होती है तो जन्मदर खुद ब खुद कम होगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और जरूरी है कि मंत्रालय, प्रेम, शादी और परिवार को लेकर लोगों में सकारात्मक भावनाएं पैदा करने के लिए सामाजिक नीतियां और प्रचार प्रसार में सुधार करें।कूलिंग-ऑफ अवधि लोगों को फिर से शादी के प्रति रुचि जगाने में मददगार साबित हो सकती है, साथ ही ये महिलाओं में भी काम के बजाए बच्चो में रुचि जगाएगी। हालांकि शादी को तोड़ने की अर्जी देने के बजाए ये वाला विकल्प मंहगा होता है साथ में इसमें समय भी लगता है।2018 में चीन की घरेलू मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक 66 फीसद तलाक से जुड़े मामले पहली सुनवाई के दिन ही खारिज हो जाते हैं। कूलिंग ऑफ अवधि लागू होने से पहले लोगों में तलाक को लेकर हड़बड़ी देखने को मिली थी।चीन अकेला देश नहीं है जहां कूलिंग ऑफ अवधि लागू हुई है, इससे पहले फ्रांस और यूके में भी आपसी सामंजस्य से तलाक लेने की प्रक्रिया में इंतजार की अवधि को 2 से 6 हफ्तों के बीच बढ़ा दिया गया था।

जॉर्ज फ्लॉयड की बरसी पर नस्ली हिंसा के खिलाफ परिजनों ने निकाला मार्च

मिनियापोलिस। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड समेत पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन, कार्यकताओं और मिनियापोलिस के नागरिकों ने फ्लॉयड की बरसी पर आयोजित मार्च में हिस्सा लिया। उत्तरी कैरोलीना में फ्लॉयड के जन्मस्थल फेयेटविले में एक गैर सरकारी संगठन जॉर्ज फ्लॉयड मेमोरियल फाउंडेशन फ्लॉयड की पुण्यतिथि पर इस सप्ताहांत और अगले की सप्ताह की शुरूआत में कई कार्यक्रम कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के तहत रविवार को एक रैली और मार्च का आयोजन किया गया। अश्वेत समुदायों के प्रति नस्ली मतभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए फ्लॉयड के परिजन ने सितंबर 2020 में गैर सरकारी संगठन शुरू किया था। फ्लॉयड की मौत को एक साल पूरा हो जाएगा।

पाकिस्तानी वायु सेना कुख्यात तुर्की अर्धसैनिक समूह को सहयोग करने को तैयार

अंकारा, (एजेंसी)। पाकिस्तानी वायु सेना (पीएएफ) एक कुख्यात तुर्की अर्धसैनिक समूह के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई है, इसपर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लीबिया में सैन्य अभियानों में भाग लेने के लिए सीरियाई सशस्त्र समूहों के लड़ाकों को तैनात करने का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तानी वायुसेना की नीति थिंक टैंक, सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, इस्लामिक यूनियन कांग्रेस का एक भागीदार बन गया है, जिसे एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। यह निजी सेना द्वारा संचालित एक संगठन है।

2020 में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने खुलासा किया कि कैसे तुर्की सरकार ने लीबिया में अपने अर्धसैनिक ठेकेदार सादात का इस्तेमाल किया और वरिष्ठ अधिकारियों के समूह द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में तुर्की के अधिकारियों से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया।

चिट्ठी में कहा गया है, तुर्की अधिकारियों ने कथित तौर पर चयन की सुविधा के लिए निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियों को अनुबंधित किया। साथ ही सेनानियों के लिए आधिकारिक और संविदात्मक दस्तावेज तैयार करने की भी बात की। इस संदर्भ में उद्धृत कंपनियों में से एक सादात इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी थी। रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सआदत ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए भर्ती करने में योगदान दिया।

इस्लामिक यूनियन कांग्रेस सभाओं की एक श्रृंखला है, जो 2017 में शुरू हुई और 2023 तक जारी रहेगी। यह आयोजन सत्ताधारी पार्टी, सरकारी एजेंसियों और तुर्की एयरलाइंस द्वारा संचालित नगर पालिकाओं द्वारा प्रायोजित है। पांचवीं कांग्रेस, जिसमें सीएएसएस एक भागीदार है, दिसंबर 2021 में इस्तांबुल में आयोजित होगी और इस्लामिक संघ (2021) के लिए संयुक्त विदेश नीति के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सीएएसएस एक नीतिगत थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2019 में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में एयरोस्पेस में विशेषज्ञता के साथ की गई थी। यह वरिष्ठ सेवानिवृत्त वायु सेना जनरलों द्वारा चलाया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में शोधकर्ता कार्यरत हैं। सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल कलीम सआदत, जिन्होंने पीएएफ में विभिन्न क्षमताओं में 38 वर्षों तक सेवा की थी, सीएएसएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दिलचस्प यह है कि सैन्य क्षेत्र में काम करने वाले दो सरकार समर्थक संगठनों के बीच सहयोग उसी समय हुआ जब तुर्की और पाकिस्तान के लड़ाकू जेट के संयुक्त निर्माण में सहयोग करने की अफवाह थी। सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि तुर्की जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है,जिसे पाकिस्तान चीन के साथ विकसित कर रहा है।

इस महीने की शुरूआत में,पाकिस्तान वायुसेना (पीएएफ) के प्रमुख मार्शल मुजाहिद अनवर खान, जो तुर्की की यात्रा पर थे, ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दो देश, एक राष्ट्र हैं, क्योंकि वे न केवल समान संस्कृति और विश्वास साझा करते हैं बल्कि समान हित भी रखते हैं। वायु प्रमुख तुर्की में एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर (एएसएसएएम) के बोर्ड सदस्यों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के 12 अधिकारियों को पृथक-वास में रहने को कहा

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। इमरान सरकार ने भारतीय उच्चायोग के 12 अधिकारियों को परिवार और वाहन चालकों सहित पृथक-वास में रहने को कहा है। दरअसल पिछले सप्ताह भारत से लौटने पर इसमें से एक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। विदेश कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बताया कि 12 अधिकारी और उनके परिजन शनिवार (22 मई) को वाघा सीमा पार करके पाकिस्तान आए थे। सभी 12 अधिकारियों के पास कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट थी, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इनकी फिर से जांच की गई। प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच में एक अधिकारी की पत्नी में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना पर पाकिस्तान की शीर्ष इकाई नेशनल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (एनसीओसी) ने मामले की समीक्षा कर सभी अधिकारियों, उनके परिजन और वाहन चालकों को पृथक-वास में रहने की सलाह दी। अधिकारी ने कहा, भारतीय उच्चायोग को एनसीओसी के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले के कहा कि दोनों देशों के बीच निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत अगर कोई राजनयिक कर्मचारी या उनका कोई सहयोगी संक्रमित पाया जाता है,तब उन्हें उनके देश वापस भेजने के बजाए उसी देश में पृथक-वास में रहना होगा।

कांगो में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हजारों लोगों ने गोमा शहर छोड़ा, 15 लोगों की मौत

गोमा, (एजेंसी)। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी फटने के बाद लावा बहकर यहां के गांवों में जा पहुंचा है, जिसके कारण यहां 500 से ज्यादा मकान नष्ट हो गए हैं और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों तथा प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी है। कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो शनिवार को फट गया था, जिसके कारण करीब पांच हजार लोग गोमा शहर छोड़कर सीमा पार रवांडा जाना पड़ा, जबकि अन्य 25,000 ने उत्तर पश्चिम में साके शहर में शरण ली। इस प्राकृतिक आपदा के बाद से 170 से अधिक बच्चे लापता हैं।

यूनिसेफ के अधिकारियों का कहना है कि वे ऐसे बच्चों की मदद के लिए शिविर लगा रहे हैं जो अकेले हैं, जिनके साथ कोई वयस्क नहीं है। यह ज्वालामुखी पिछली बार वर्ष 2002 में फटा था तब भी यहां भारी तबाही मची थी। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी तथा 1,00,000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। एलिने बिचिकवेबो ने बताया लावा आने पर वह अपने बच्चे को लेकर निकल गई, लेकिन अपने माता-पिता को नहीं बचा सकी। वह कहती हैं, मुझे मदद की जरूरत है क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। हम एकदम अनाथ हो गए हैं।

बगाम्बा गांव में लावा की चपेट में आए मकान अभी भी जल रहे हैं। एक अन्य निवासी एलम्बा सुतोये ने कहा, लोग घबराए हुए हैं और भूखे हैं। उन्हें नहीं पता कि रात वे कहां गुजारेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच गोमा से निकलने की कोशिश के दौरान ट्रकों के बीच हुई टक्कर में कम से कम पांच अन्य लोग मारे गए हैं। शहर के निकट बुहेने क्षेत्र में जमा हुआ लावा अब भी धधक रहा है और उसमें से धुंआ निकल रहा है।

कोरोना वायरस फैलने से एक माह पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार

वाशिंगटन, (एजेंसी)। कोरोना वायरस को दुनियाभर में फैले अब करीब डेढ़ साल हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी लोगों की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई हैं। इस बीच, कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बा फिर से चीन पर केंद्रित कर दिया है। एक अमेरिकी खुफि या रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनियाभर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब एक महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के तीन शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। एक अमेरिकी अखबार की खबर के मुताबिक, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरॉलजी के तीन शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिका की इस खुफि या रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार शोधकताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय और अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी गई हैं।

अमेरिका की ओर से जारी इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये खुफिया जानकारियां उस दावे की जांच दोबारा कराने पर बल देंगी जिनमें वुहान लैब से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई गई है। अमेरिका की ओर से यह खुफिया रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) एक बैठक करने जा रहा है जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में अगले चरण की जांच पर चर्चा का अनुमान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए वुहान गई थी। वहां कई महीनों तक जांच दल ने इसको लेकर पड़ताल की। इस दौरान वे चीन की वुहान लैब भी गए। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं है कि कोरोना वायरस, वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस और वुहान वायरस कहते थे और चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने चीन पर जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को पूरा सहयोग न देने और वुहान लैब से जुड़ी जानकारियां छिपाने के आरोप भी लगाए थे।

इससे पहले पता चला था कि चीन में मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से प्रयोग चल रहे थे। ये प्रयोग वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चल रहे थे और इनमें बैट लेडी नाम से ख्यात महिला विज्ञानी शी झेंग-ली शामिल थी। शी अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रमुख कोरोना वायरस शोधकर्ता राल्फ एस बारिक के साथ भी काम कर रही थी।

कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक जितनी भी आशंकाएं जताई गई हैं, उनमें सबसे पुख्ता वुहान की लैब से उसके बाहर आने की है। यह मानना है विज्ञान के मामलों के प्रमुख लेखक निकोलस वाडे का। एटॉमिक साइंटिस्ट्स के बुलेटिन में वाडे ने लिखा है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने की आशंका सबसे ज्यादा है। क्योंकि पूरे चीन में वह इकलौती लैब है जहां पर कोरोना वायरस पर शोध चल रहा था। यहां पर चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदलकर उसका मानव कोशिकाओं पर प्रभाव देखा जा रहा था। ये प्रयोग दक्षिण चीन स्थित युन्नान की गुफाओं में रहने वाले सैकड़ों प्रजातियों के चमगादड़ लाकर उनके भीतर के वायरस निकालकर किए जाते थे।

कांगो के हजारों लोगों ने ज्वालामुखी फूटने पर रवांडा में शरण ली और वहां की सड़कों पर रहे।

फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना किया : केजरीवाल

नई दिल्ली (आनंद राय) ।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना कर दिया है क्योंकि वे केंद्र से सीधे तौर पर बात करना चाहती हैं। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, हमने फाइजर और मॉडर्ना के साथ बात की थी। उन्होंने कहा कि वे हमें टीके नहीं देंगे और सीधे केंद्र के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन कंपनियों के साथ बात कर टीकों का आयात करें और उन्हें राज्यों के बीच वितरित करें। केजरीवाल की टिप्पणी के एक दिन पहले पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि मॉडर्ना ने सीधे राज्य सरकार को टीके देने से इनकार करते हुए कहा है वह केवल केंद्र के साथ बात करेगी। केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर धीरे-धीरे घट रही है और दिल्ली सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट चुकी है। उन्होंने कहा, हमने चीन से 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किये हैं। तीन डिपो तैयार किए जा रहे हैं, जहां दो-दो हजार सिलेंडर होंगे। तीसरी लहर में इनका इस्तेमाल होगा। विदेश मंत्रालय और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इसमें बहुत मदद की, वरना यह संभव नहीं होता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि फाइजर और मॉडर्ना ने टीके सीधे दिल्ली सरकार को बेचने से मना कर दिया है। सिसोदिया ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में टीके खत्म होने के बाद 18 से 44 साल आयुवर्ग के लोगों के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वहीं, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों के लिए कोवैक्सीन के केंद्रों को भी टीकों की कमी के कारण बंद किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इस समय टीकाकरण बहुत जरूरी है और उन्होंने मॉडर्ना, फाइजर तथा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनियों से टीकों के लिए बात की है। उन्होंने कहा, फाइजर और मॉडर्ना ने हमें सीधे टीके बेचने से इनकार कर दिया है और बताया है कि वे केंद्र से बात कर रही हैं। केंद्र ने फाइजर और मॉडर्ना को मंजूरी नहीं दी है वहीं पूरी दुनिया में इन्हें मंजूरी दी गयी है, और कई देशों ने इन टीकों की खरीदारी की है। सिसोदिया ने कहा कि कुछ देशों ने परीक्षण के स्तर पर ही टीकों को खरीद लिया लेकिन भारत ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

वैक्सीनेशन कार्यक्रम का केंद्र के वैक्सीन कुप्रबंधन की वजह से बना मजाक : सिसोदिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष दिल्ली में वैक्सीन की कमी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया साथ ही वैक्सीन को उपलब्ध न करवाने और खराब वैक्सीन मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मजाक बना कर रख दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है। आज पूरे विश्व की सरकारें अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने में युद्धस्तर पर जुटी हुई है, दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां की। दिल्ली में 18-45 आयुवर्ग के लिए 400 और 45+ आयुवर्ग के लिए 650 वैक्सीन सेंटर स्थापित किए गए लेकिन केंद्र की बदइंतजामी और वैक्सीन की कमी से दिल्ली में युवाओं के लिए शुरू किए गए केंद्रों को बंद करना पड़ा है साथ ही 45+ आयुवर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी से कोवैक्सीन के सेंटर बंद करने पड़े है। ये हाल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है कई राज्यों के कई जिलों में वैक्सीन न मिलने से युवाओं के लिए केंद्रों की शुरूआत भी नहीं कि गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कमी होने के कारण आज भारत कोरोना की इतनी मार झेल रहा है इसके लिए केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल हो चुकी है। जब दिल्ली सरकार ने केंद्र से युवाओं के लिए वैक्सीन मांगी तो केंद्र ने सिर्फ 4 लाख वैक्सीन देकर बोला कि बाकी वैक्सीन के लिए फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों के साथ ग्लोबल टेंडर जारी करो। जब दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए इन कंपनियों से बात की तो जबाब मिला कि वे केवल केंद्र से वैक्सीन को लेकर डील करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मजाक बना रखा है। केंद्र सरकार को इस संकट को लेकर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में जो वैक्सीन सफल साबित हो रही है केंद्र ने अबतक भारत में उन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने दिसंबर 2020 में ही फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन भारत में अबतक इनमें से किसी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई। रूस ने भी अगस्त 2020 में ही स्पुतनिक को मंजूरी दे दी थी और दिसंबर में अपने यहां मास-वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज 68 देशों ने स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दे रखी है लेकिन केंद्र सरकार की नींद महीनों बाद खुली है और अप्रैल 2021 में जाकर भारत सरकार ने स्पुतनिक को मंजूरी दी। ब्रिटेन ने भी फाइजर को दिसंबर में मंजूरी दे दी और 85 अन्य देश फाइजर को अपने यहां मंजूरी दे चुके है लेकिन भारत में इसे मंजूरी नहीं मिली है। भारत के अलावा मोडर्ना को 46 देशों ने और जॉनसन एंड जॉनसन को 41 देशों ने मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को मजाक बना रखा है। एक ओर केंद्र राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर लाने के लिए कहती है दूसरी ओर विदेशी वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं देती है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व ने वैक्सीन के उत्पादन पर नजर बनाए रखा था और वैक्सीन के लिए एडवांस आर्डर कर दिया था उस दौरान केंद्र सरकार गहरी नींद में सो रही थी। एक आंकड़े के अनुसार नवंबर 2020 तक अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अपने लिए 70 करोड़ वैक्सीन का आर्डर दे दिया था। आज अमेरिका के पास अपने सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त वैक्सीन है। ब्रिटेन के पास भी जनवरी में ही अपनी 75% आबादी के लिए वैक्सीन उपलब्ध था। लेकिन केंद्र सरकार अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जगह उसका निर्यात करने में लगी रही। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया उसके बाद से अप्रैल तक सरकार की ओर से स्क्क्को कोई फण्ड नही दिया गया। और आज जब देश में राज्य वैक्सीन की मांग कर रहे है तो भाजपा के लोग ऊटपटांग बयान देते है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए गंभीरता से कदम उठाए। और एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका निभाकर विदेशी वैक्सीनों को मंजूरी दे और राज्यवार राजनीति से ऊपर उठे।

12वीं परीक्षा अगस्त तक टालने से कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया होगी प्रभावित : प्रधानाचार्य

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अगर 12वीं बोर्ड की परीक्षा जुलाई-अगस्त में कराने और मूल्यांकन प्रकिया सितंबर तक करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे महाविद्यालयों में प्रवेश की समयसारिणी बाधित होगी और उन विद्यार्थियों की योजना प्रभावित हो सकती है जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने यह राय व्यक्त की है। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा की परीक्षा 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच कराने और नतीजे सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। बोर्ड ने रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में दो विकल्प भी प्रस्तावित किए हैं, पहला कि निर्धारित केंद्रों पर केवल अहम विषयों की परीक्षा कराई जाए, दूसरा कि विद्यार्थी जहां पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में कम अवधि की परीक्षा कराई जाए। दिल्ली के रोहिणी स्थित एमआरजी स्कूल के निदेशक रजत गोयल ने कहा, नए प्रस्ताव से शिक्षा जगत में नई परेशानी उत्पन्न होगी। बोर्ड परीक्षा में देरी करने से कॉलेजों में आवेदन करने की तारीख में भी देरी होगी और यही परिपाटी प्रवेश एवं शैक्षणिक सत्रों में भी देखने को मिलेगी। अगर बोर्ड परीक्षा और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बीच उचित अंतर नहीं होगा तो विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की स्थिति का पूवार्नुमान नहीं लगाया जा सकता। हम कभी निश्चित नहीं हो सकते कि उस समय स्थिति क्या होगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा और उसके बाद नतीजों में देरी का सुझाव नहीं दिया जा सकता। परीक्षा में देरी से विद्यार्थी एक बार फिर मानसिक दबाव में चले जाएंगे जिसका दुष्प्रभव पड़ सकता है। गुरुग्राम के एक शीर्ष स्कूल की प्रधानचार्या ने पहचान जाहिर नहीं करते हुए बताया कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का शैक्षणिक सत्र आमतौर पर सितंबर में शुरू होता है।

कांग्रेस नेता गुड्डी गुप्ता को मिली जमानत

(एजेंसी)

नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले के ब्रह्मपुरी इलाके में पिछले 20 मई को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े को बीच बचाव में आई कांग्रेस नेता गुड्डी गुप्ता के ऊपर पुलिस द्वारा एससी एसटी के तहत एफ आई आर दर्ज कर जेल भेज दिया गया था लेकिन अदालत द्वारा कांग्रेस नेता गुड्डी गुप्ता को बेल दे दिया गया, और वो अब जेल से बाहर हो गई है। आपको बताते चलें कि ब्रह्मपुरी में 20 मई को दो अन्य व्यक्तियों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर कहासुनी होते देख कांग्रेस नेता गुड्डी गुप्ता ने समझौते के लिए उन दोनों के बीच पहुंची पहुंचते ही एक व्यक्ति ने गुड्डी गुप्ता के वहां पहुंचते ही उस पर आरोप लगा दिया कि हमें कांग्रेस नेता गुड्डी गुप्ता ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया पुलिस ने इस बयान के तहत गुड्डी गुप्ता के ऊपर जातिसूचक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दी, लेकिन आज अदालत ने गुड्डी गुप्ता को बेल दे कर जेल से आजाद कर दिया।

मास्टर प्लान 2041 में दिल्ली के गांवों की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने पर होगा जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के आगामी 20 वर्ष के विकास के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान-2041 का खाका दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ अर्बन एफेयर्स (एनआईएयू) ने तैयार कर लिया है। जिसे आने वाले दिनों में उपराज्यपाल समेत केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण और एनआईएयू की ओर से एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन तैयार कर ली गई है। जिसे उपराज्यपाल के समक्ष पेश करने के बाद एक 45 दिनों के लिए आम जनता के समक्ष सुझाव एवं आपत्तियों के लिए रखा जाएगा। आने वाले सप्ताह में डीडीए और एनआईएयू के अधिकारियों की बैठक उपराज्यपाल के साथ होने की संभावना है। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक, नए मास्टर प्लान में दिल्ली के अविकसित-अनधिकृत इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान पास को अनुमति मिलने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। मास्टर प्लान-41 के लिए बनाए गए प्राथमिकता स्केल में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। जिसके लिए न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी स्तर पर बढ़ावा देना है। मास्टर प्लान-41 में दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी व अन्य प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। जिससे ऐसी सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को दिल्ली में ही बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

कोरोना के मरीजों के लिए 487 वेंटिलेटर बेड खाली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन बेड बल्कि वेंटिलेटर बेड भी खाली हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली कोरोना एप पर राजधानी में कोरोना के मरीजों के लिए 487 वेंटिलेटर बेड खाली होने की जानकारी दी गयी है। खाली वेंटिलेटर की पड़ताल के चार अस्पतालों में कॉल कर स्थिति जानने की कोशिश की। इनमें से तीन अस्पतालों ने दिल्ली कोरोना एप के मुताबिक ही वेंटिलेटर बेड खाली होने और मरीज को उपलब्ध कराने की बात कही लेकिन लोकनायक अस्पताल में वेंटिलेटर बेड खाली न होने की जानकारी दी गई। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक में 70 खाली वेंटिलेटर बेड होने की जानकारी दिल्ली कोरोना एप पर दी गई है। एप के मुताबिक यहां वेंटिलेटर क्व कुल 300 बेड हैं। इनमें से 230 पर मरीज भर्ती हैं और 70 खाली हैं। अस्पताल के हेल्पडेस्क पर फोन किया तो वहां मौजूद ऑपरेटर ने वेंटिलेटर की जानकारी पता करने के लिए कॉल को किसी अन्य नम्बर पर रेफर कर दिया। वहां फोन उठाने वाले शख्स ने बताया कि यहां वेंन्टीलेटर बेड खाली नहीं है। जब यह कहा गया कि एप पर 70 खाली वेंन्टीलेटर बेड दिखाए गए हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि आईसीयू खाली है वेंटिलेटर नहीं।दिल्ली के पूर्वी इलाके में स्थित गुरू तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 80 वेंन्टीलेटर बेड खाली होने की जानकारी दी गयी है। यहां कोरोना के मरीजों के लिए 208 वेंटिलेटर बेड हैं इनमें से 128 भरे हुए हैं। अस्पताल में हेल्पडेस्क पर फोन किया गया तो वहां मौजूद ऑपरेटर ने बताया कि अगर मरीज को जरूरत होगी तो उसे वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आप मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर आ सकते हैं राजधानी दिल्ली के डा. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार के कोविड जनसंवाद ऐप के अनुसार कुल हॉस्पिटल में कुल वेंटिलेटर बेड्स की संख्या 142 है जिसमें से 32 वेंटिलेटर बेड्स अभी खाली हैं। डा. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर बताया गया की हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड्स खाली हैं। कोरोना से संक्रमित जिस मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता है उस मरीज को सीधा अस्पताल लेकर आएंगे तो वेंटिलेटर बेड आसानी से मिल जाएगा।

दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया राशन दुकानों का औचक निरीक्षण, मिली कई अनियमितताएं

नई दिल्ली । दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत लाभार्थियों को हस्त्र और क्लन्यङ्ग के तहत मई 2021 के महीने के लिए मुफ्त में राशन की उपलब्धता और वितरण की जांच के लिए मुस्तफाबाद क्षेत्र में राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। कुछ शिकायतें थीं कि क्षेत्र के कुछ एफपीएस डीलर नियमित रूप से और समय पर राशन की दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इस पूरे निरीक्षण के दौरान मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस, खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त और खाद्य इंस्पेक्टर भी मंत्री के साथ थे। निरीक्षण के दौरान, खाद्य मंत्री ने दो राशन दुकानों को बंद पाया। एफपीएस डीलरों ने दुकान तभी खोला जब उन्हें मंत्री के साथ गई प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर बुलाया गया। मंत्री ने एफपीएस डीलरों को बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक एफपीएस खोलने के संबंध में खाद्य विभाग के निर्देशों का पालन करने और खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एफपीएस डीलरों को चेतावनी भी दी कि विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री के साथ गए एफ एंड एस विभाग की टीम ने एक अन्य एफपीएस डीलर द्वारा स्टॉक और निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ अनियमितताएं पाईं। खाद्य विभाग की टीम द्वारा निर्देशित किए जाने पर स्त्रक्क डीलर प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इमरान हुसैन ने मामले को गंभीरता से लिया और निरीक्षण दल को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड को जब्त करने सहित एफपीएस डीलर के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को एफपीएस डीलर के खिलाफ विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इमरान हुसैन ने चेतावनी दी कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो अवैध रूप से खाद्यान्न एकत्र करते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं। इसके अलावा जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली में कोविड नामित LNJP अस्पताल के पास भोजन प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद लोग कतार में खड़े हैं।

बिना राशन कार्ड के राशन पाने के लिए इस हफ्ते से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में लॉकडाउन के रोजाना कमाकर खाने वालों को भूखे ना रहना पड़े इसलिए सरकार ने दिल्ली में ऐसे लोगों को भी राशन देने का फैसला किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस सप्ताह इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा।

कुछ सरकारी तकनीकी मंजूरी मिलने के साथ यह पंजीकरण खोल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस श्रेणी में राशन पाने के लिए किसी भी तह की आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उसे इसके लिए ई-कूपन बनेगा। उसे दिखाने मात्र से ही उसे राशन दे दिया जाएगा। जो भी यह ई-कूपन पंजीकरण करके प्राप्त करेगा उसे राशन दिया जाएगा। इसके तहत उसे 4 किलो गेंहू, एक किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। उसके बदल कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बताते चले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीन दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 17.50 राशनकार्ड से करीब 72 लाख लोगों को राशन मिलता है। मगर दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग है जो कि बाहर से आकर रहते है। रोज कमाकर खाते है। लॉकडाउन में ऐसे लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने के लिए इसी सप्ताह पंजीकरण के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप, सरकार के इशारे पर निजी अस्पताल कर रहे हैं मनमानी

नई दिल्ली । निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों मनमाने तरीके से पैसे वसूलने के लिए भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा इन पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। उसने दिल्ली सरकार से ज्यादा बिल वसूलने की शिकायतों की जांच कराने और लोगों के पैसे वापस दिलाने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले लगभग 15 माह से निजी अस्पताल वाले मनमानी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जून में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुल्क निर्धारित किए थे। साधारण आइसोलेशन बेड के प्रतिदिन आठ से दस हजार रुपये, बिना वेंटिलेटर वाले आइसीयू बेड के 13 से 15 हजार रुपये और वेंटिलेटर वाले बेड के 15 हजार से 18 हजार रुपये निर्धारित किए गए थे। इसके विपरीत पिछले दिनों आइसीयू बेड के लिए एक से डेढ लाख रुपये प्रतिदिन वसूले जा रहे थे। इस तरह की शिकायतों के बावजूद दिल्ली सरकार चुप रही। दिल्ली में आयुष्मान योजन नहीं लागू की गई। यदि यह लागू होती तो कई मरीजों को इलाज में दिक्कत नहीं होती। सरकार ने जानबूझकर यह योजना लागू नहीं की जिससे कि निजी अस्पताल वाले मनमानी कर सकें। उन्होंने निजी अस्पतालों की आडिट कराने की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अस्पतालों में तैनात नोडल अधिकारी मरीजों की सहायता करने के बजाय सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। पैसे लेकर मरीजों को बेड, आक्सजीन व वेंटिलेटर दिए जा रहे थे। लोगों की शिकायत के बावजूद किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

संपादकीय

कहीं भी ऑक्सीजन कम न हो

कोविड-19 की बीमारी में अब तक तीन तरीके बड़े स्तर के निदान संबंधी परीक्षणों में खरे उतरे हैं। पहला, डेक्समेथासोन का इस्तेमाल, दूसरा, खून पतला करने की दवाएं देना और तीसरा, ऑक्सीजन-सपोर्ट। (हां, यह सच है कि कोविड-19 में ऑक्सीजन एक इलाज या दवा है।) इसके अलावा बाकी दवाएं जैसे प्लाज्मा थेरेपी, इवेरमेक्टिन और रेमडेसिविर अधिकतर बड़े बहुदेशीय निदान संबंधी परीक्षणों में प्रभावकारी नहीं पाए गए हैं। अलबत्ता, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन-सपोर्ट शुरुआत से ही एक मान्य तरीका रहा है। कोविड-19 के कुल मरीजों में से 15 से 20 फीसदी को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और उनमें से भी कुछ को ही ऑक्सीजन-सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए भारत में पहली लहर में जब सक्रिय मामले बढ़ने लगे, तब चिकित्सा-ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी। नतीजतन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति बनाई और स्वास्थ्य की स्थाई संसदीय समिति में इस पर चर्चा भी हुई। चिकित्सकीय-ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी, लेकिन मामला काबू में रहा। मगर कोविड की इस दूसरी लहर में हालात हाथ से बाहर निकल गए। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि कोरोना की पहली लहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 10.5 लाख के करीब थी, लेकिन दूसरी लहर में यह संख्या 3.5 गुना तक बढ़ गई। आज देश भर में 37 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। फिर, यह भी देखा गया कि पिछली लहर की तुलना में इस बार आनुपातिक रूप से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। यानी, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी और ऑक्सीजन-सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों का अनुपात भी। इसका नतीजा यह हुआ कि चिकित्सकीय-ऑक्सीजन के लिए देश भर में बदहवासी का आलम पैदा हो गया। ऐसा नहीं है कि भारत में ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा। रोजाना 7,000-8,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम बना रहे हैं। कोविड-19 महामारी से पहले 30 फीसदी से भी कम ऑक्सीजन चिकित्सा-कार्य के लिए इस्तेमाल होती थी, शेष औद्योगिक कामों में खपत होती। लेकिन जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, तब दो मुख्य चुनौतियां उभरकर सामने आईं। पहली, औद्योगिक ऑक्सीजन संयंत्रों को चिकित्सकीय-ऑक्सीजन बनाने के लिए विशेष तैयारियों और समय की जरूरत थी। और दूसरी, देश के कुछ ही राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जहां से जरूरतमंद राज्यों तक इसे लाने के लिए पर्याप्त विशेष टैंकर नहीं थे। निश्चित ही, इनसे निपटने के लिए पहले से योजना तैयार होनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं हो सका। महामारी एक राष्ट्रीय आपदा होती है, इसलिए इससे निपटने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। उसको इस बाबत समय पर योजना बनानी चाहिए थी और उसका बेहतर क्रियान्वयन भी करना चाहिए था। मगर राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकतीं। ऑक्सीजन का वितरण सही तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि राज्य अपने यहां कोरोना के आंकड़े दुरुस्त रखते और सही संख्या केंद्र को बताते। जिन-जिन राज्यों में कम मामले सामने आए, वहां नियमानुसार कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। पर चूंकि इन राज्यों में वास्तविक मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा थी, इसलिए शत-प्रतिशत आपूर्ति होने के बाद भी, असलियत में जमीनी स्तर पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। देश में चिकित्सकीय-ऑक्सीजन की कमी का मसला एक और बड़े तथ्य की ओर इशारा करता है। राज्य सरकारें बेशक दावा करती हैं कि अपने-अपने अस्पतालों में वे मुफ्त में दवा और मरीजों की जांच की व्यवस्था करती हैं, मगर असलियत में ऐसा होता नहीं। मरीजों को न दवाएं मिलती हैं और न उनकी पर्याप्त जांच हो पाती है। देश भर में सरकारी अस्पतालों के बाहर निजी दवाई दुकानदार और नैदानिक केंद्रों की लंबी कतारें इसके सुबूत हैं। ऑक्सीजन भी एक दवाई है, और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति में भी वे सारी बातें इस पर लागू होती हैं, जो अन्य दवाओं पर लागू होती हैं। चूंकि निजी दवा दुकानदारों के पास भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया। अगर लोगों को आसानी से यह मिल जाता, तो शायद ऑक्सीजन की कमी का इतना हो-हल्ला नहीं मचता। इसलिए अगर हम इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें सरकारी स्वास्थ्य-तंत्र में दवा आपूर्ति और वितरण में आमूल-चूल सुधार करने पड़ेंगे। इसके फंड बढ़ाने होंगे, आपूर्ति-श्रृंखला को दुरुस्त करना होगा और इससे जुड़े लोगों को नियमित तौर पर प्रशिक्षण भी देना होगा। जाहिर है, बेहतर प्लानिंग और उचित वितरण की जरूरत है। यह सही है कि तीन-चार सप्ताह पहले अपने यहां जो परिस्थितियां थीं, उनमें कुछ सुधार हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नेशनल टास्क फोर्स गठित की है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी ऑक्सीजन की जरूरत, इस्तेमाल और वितरण पर सुझाव देना है। मगर हमें कोरोना की अगली लहर के लिए भी अभी से तैयार होना चाहिए। इसके लिए विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है। हमें अपने आसपास यह देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से ऑक्सीजन के वितरण को सुनिश्चित किया गया। महाराष्ट्र के नानदरबार के जिलाधिकारी ने छह-आठ महीने पहले ही अस्पतालों में ऑक्सीजन-प्लांट लगवा दिए थे। मुंबई नगर निगम ने भी लगभग यही किया, साथ ही नियंत्रण कक्ष बनाकर पूरे मुंबई को छह हिस्सों में बांट दिया व केंद्रीकृत व्यवस्था करते हुए सभी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। केरल ने भी फरवरी में ही ऑक्सीजन की कमी को भांप लिया था और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। नतीजतन, वहां भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर मारामारी नहीं हुई। आने वाले दिनों में नए ऑक्सीजन-प्लांट लगने, आपूर्ति-व्यवस्था में सुधार आने, ऑक्सीजन-कंसंट्रेटर के उपलब्ध होने और नए मरीजों की संख्या में कमी आने से स्थिति में सुधार होगा। हमने कोविड-19 की दूसरी लहर में चिकित्सकीय-ऑक्सीजन आपूर्ति में जिन कठिनाइयों, चुनौतियों, परेशानियों और नुकसान का सामना किया है, उनकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन इनसे सबक लेकर अगर केंद्र और राज्य सरकारें मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त जांच योजनाओं को सुदृढ़ करती हैं और उनको शब्दश: लागू करती हैं, तो हम यकीनन एक सभ्य और नैतिक समाज गढ़ पाएंगे।

प्रवीण कुमार सिंह

कोरोना जैसी भयावह आपदा का सामना जीवनशैली में बदलाव से ही संभव

> वे प्रधानमंत्री को ही मुख्य अभियुक्त सिद्ध करने पर आमादा हैं। मोदी विरोधी दलतंत्र भी इसी रास्ते पर है। ऐसा रवैया दुखद है। आपदा में मतभेद भुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीवनशैली के भारतीय स्वरूप एवं संस्कृति के विरोधी है। संकट के समय सारे मतभेद भुलाकर मिल-जुलकर ही इस आपदा से लड़ना चाहिए। वे इतने भर से ही देश का बहुत भला कर सकते हैं। अनेक गैर-राजनीतिक संगठन व उद्यमी इस संकट में लगातार सहायता कर रहे हैं। आपदा में सहायता भारतीय शैली का अंग है। यह आपदा जानलेवा है तो भी चिकित्सक और पुलिस बल के लोग जिंदगी की परवाह न करते हुए युद्धरत हैं।

जीवनशैली जड़ नहीं होती। इस पर वैज्ञानिक शोध, संस्कृति व दर्शन के प्रभाव पड़ते रहते हैं। युद्ध और दीर्घकालिक सत्ता भी जीवनशैली पर प्रभाव डालते हैं। महामारियों के प्रभाव भी व्यापक होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण वाले चीन की जीवनशैली पर कम्युनिस्ट सत्ता का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत की जीवनशैली पर मुगल सत्ता का भी गहरा असर पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन ने भारत की जीवनपद्धति, कला-साहित्य और रहन-सहन को भी राष्ट्रवादी बनाया था। भारत की जीवनशैली गतिशील और परिवर्तनशील है। इस जीवनपद्धति में गजब की आत्म रूपांतरण शक्ति है। प्लेग, फ्लू जैसी विश्वव्यापी महामारियों से जूझते हुए भारत ने विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। अकाल की परिस्थिति भी भयानक थी, लेकिन भारत के लोगों ने धीरज नहीं खोया। संप्रति कोविड-19 की जानलेवा चुनौती है। हम अपने 2.38 लाख से ज्यादा लोगों को खो चुके हैं। अस्पतालों में बेड नहीं। आक्सीजन आपूर्ति तंग है। जरूरी दवाओं की किल्लत है। सरकारें युद्धरत हैं, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालकर अपने नागरिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। भयावह परिस्थिति का सामना जीवनशैली में बदलाव लाकर ही संभव है।

भारत में कोरोना का हमला जनवरी 2020 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल सक्रियता दिखाई। उन्होंने लॉकडाउन किया। जनजागरण के हरसंभव प्रयास किए गए। कोरोना से थोड़ी राहत मिली। संयम टूटा। यह संयम जीवनशैली का भाग नहीं था। अन्यथा ऐसी क्षति न होती। दूसरी लहर पहले से ज्यादा प्राणलेवा है। केंद्र पूरी ताकत के साथ जूझ रहा है। वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। शनिवार को ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पेश की गई एक दवा उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। यहां दुनिया

का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। आक्सीजन आपूर्ति के तमाम उपाय जारी हैं। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही बहुत कमजोर है। भारत में प्रति 10 हजार व्यक्तियों पर अनुमानित 8.6 चिकित्सक हैं। प्रति 10 हजार पर लगभग 6 बेड हैं। वेंटिलेटर वाले बेड तो और भी कम हैं। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जनस्वास्थ्य की घोर उपेक्षा की।

जीवनशैली में यथापरिस्थिति परिवर्तन भारत की प्रकृति है। शीत ऋतु आती है। हम परिधान बदल लेते हैं। गर्मी में लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर से जरूरी काम के लिए ही निकलते हैं। वर्षा में भी घर को वरीयता देते हैं। परिस्थिति के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। कोहरे के समय रात्रि में आवाजाही घट जाती है। भोजन भी ऋतु और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जीवनशैली में बदलाव के लिए कोई सरकारी आदेश जारी नहीं होते। सभी मनुष्य प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी अपेक्षित थी। शिष्टाचार में हाथ मिलाने से भी बचने का आग्रह किया गया। भारतीय जीवनशैली में इसका विकल्प नमस्कार है। सभी संक्रामक रोगों में दूरी बनाए रखने के फायदे हैं। मास्क लगाने पर लगातार बल दिया जा रहा है। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए इनका अनुपालन जरूरी है। अनेक लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को जीवनशैली का हिस्सा बनाया है तो तमाम ऐसे भी रहे जो असाधारण परिणाम देने वाले इन साधारण उपायों को भी नहीं स्वीकार करते। पुलिस जीवनशैली नहीं बदल सकती। इसके लिए स्वयं का प्रयास ही फलदायी है।

कोरोना पर अनेक शोध हो रहे हैं। वे उपयोगी हैं। मानवता की आशा हैं, लेकिन आमजनों को भयाक्रांत भी करते हैं। देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने गत बुधवार को चेताया था कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने कहा कि आवश्यक उपाय कर उसे टाला भी जा सकता है। यानी हमें इस महामारी से अनिश्चितकाल तक जूझना पड़ सकता है। ऐसे में जीवनशैली में बदलाव अपरिहार्य हो गया है। कोरोना बचाव के नियमों को जीवन अनुशासन का भाग बनाना होगा। इनका स्वत: स्फूर्त अनुपालन दूसरों के लिए प्रेरक भी बनेगा। कोरोना से उपजे भय से मुक्ति के लिए नकारात्मक विचारों की जगह आस्तिक भावना की वृद्धि सनातन भारतीय जीवनशैली है। जीवनशैली किसी भी समाज की मुख्य प्रेरणा है। कोरोना की परिस्थिति और चुनौती के अनुसार जीवनशैली में परिवर्तन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह परिवर्तन दिखाई भी पड़ना चाहिए।

भारत उत्सव प्रिय देश है। उत्सवों पर भारी भीड़ जुटती है। ऐसी भीड़ कोरोना अनुशासन को तार-तार करती है। पूर्वजों ने गहन अध्ययन के बाद ही उत्सवों और तीर्थाटन की रचना की थी। तब परिस्थितियां भिन्न थीं। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। हम सबको भी उसी सजगता के साथ भीड़ न जुड़ने की जीवनशैली का विस्तार करना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस संकल्प से प्राण रक्षा है। लखनऊ में मुस्लिम विद्वानों ने ईद पर पांच लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। यह स्वागतयोग्य है। सरकारों ने विवाह समारोहों में भी उपस्थिति घटाई है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में जुटने वाली भीड़ निराशाजनक है। दलों ने आत्म-अनुशासन विकसित नहीं किया।

परंपरागत भारतीय जीवनशैली स्वास्थ्य केंद्रित है। महामारी ने वैसे भी जीवनशैली को काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन यह बदलाव भय आधारित है। हम सबको स्वयं जरूरी बदलाव करने चाहिए। आपदा बड़ी है। सबने अपने मित्र और आत्मीय खोए हैं और अनेकों ने परिजन भी।

राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, लेकिन कथित उदारवादियों के लिए यह केंद्र की आलोचना का मुफीद मौका है। वे प्रधानमंत्री को ही मुख्य अभियुक्त सिद्ध करने पर आमादा हैं। मोदी विरोधी दलतंत्र भी इसी रास्ते पर है। ऐसा रवैया दुखद है। आपदा में मतभेद भुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीवनशैली के भारतीय स्वरूप एवं संस्कृति के विरोधी है। संकट के समय सारे मतभेद भुलाकर मिल-जुलकर ही इस आपदा से लड़ना चाहिए। वे इतने भर से ही देश का बहुत भला कर सकते हैं। अनेक गैर-राजनीतिक संगठन व उद्यमी इस संकट में लगातार सहायता कर रहे हैं। आपदा में सहायता भारतीय जीवन शैली का अंग है। यह आपदा जानलेवा है तो भी चिकित्सक और पुलिस बल के लोग जिंदगी की परवाह न करते हुए युद्धरत हैं। जीवनशैली में बदलाव भारत के प्रत्येक जन का कर्तव्य है।

भाजपा बंगाल जैसे राज्य में उदार हिंदुत्व के जरिये ही पैठ बना सकती है

पश्चिम बंगाल की हार के बाद भाजपा को यह समझना होगा कि मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान रखने वाले समाजों में धार्मिक प्रतिबद्धता का स्वरूप बदलता जाता है। लिहाजा जय श्रीराम का जो चुनावी घोष उत्तर भारत के राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में असर रखता है, वह बंगाल और केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में प्रभावी नहीं। बंगाल जनादेश के विश्लेषण से स्पष्ट दिखेगा कि ऐसे राज्यों में राजनीतिक पैठ तब तक नहीं होगी, जब तक सामाजिक स्तर पर पार्टी उस समाज में दूध-पानी की तरह नहीं मिलेगी। बंगाल में तोलाबाजी एक हकीकत और भोगा हुआ यथार्थ है, लेकिन उससे भी एंटी-इनकंबेंसी नहीं पैदा हुई, क्योंकि तृणमूल से आयातित नेताओं को चुनाव में सिरमौर बनाने से बड़ी और स्पष्ट विचारधारा वाली पार्टी के प्रति जनता की विश्वसनीयता घटी। समाज से घुलने-मिलने का काम प्रारंभिक दौर में भाजपा के बूते का नहीं। यह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है। बंगाली मानुष के दुख-सुख में शामिल होना, सेवा कार्य करना, अलग-अलग सामाजिक पहचान वाले समूहों के लिए प्रकल्प बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक जीवन में पैठ बनाने के लिए वर्षों तक काम करना होता है। यह काम मोदी और शाह के एक दिन में कई रैलियों से नहीं होगा। यह काम स्थानीय कार्यकर्ताओं को ठुकरा कर आयातित लोगों को टिकट देने से भी नहीं होगा। इसके उलट असम एक उदाहरण है, जहां संघ के दो दशक से ज्यादा के सेवा-कार्यों का प्रतिफल था भाजपा का सत्ता में आना। तमिलनाडु और आंध्र में पार्टी ने एम. वेंकैया नायडू को लगाकर कई साल तक कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। केरल में संघ प्राणपण से लगा हुआ है, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलने में अभी काफी समय लगेगा। जब-जब वहां कट्टर हिंदूवादी छवि वाले भाजपा के नेता प्रचार में जाएंगे, ईसाई समुदाय छिटक जाएगा। करीब 80 प्रतिशत हिंदू आबादी के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को पिछले आम चुनाव में लगभग 36 प्रतिशत मत मिले। 2009 तक इस पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि 1998 के 25 प्रतिशत के बाद से 2009 तक लगातार पार्टी का मत-प्रतिशत तक घटता ही रहा। मोदी की आंधी में भी 2019 में आधे से अधिक हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। अन्य धर्मों से अलग सनातन धर्म मूल स्वरूप में उदारवादी है। इसमें आराध्य-देव की निंदा करके भी आप अनुयायी रह सकते हैं। एक आकलन के अनुसार देश में कट्टर हिंदुओं की संख्या करीब 15-20 प्रतिशत है, शेष उदारवादी हैं। कट्टर हिंदुत्व का रूप मजबूत सांस्कृतिक पहचान वाले राज्यों में नाराजगी का कारण बनता है। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर हाल के विधानसभा चुनाव तक भाजपा ऐसी बातें करती रही कि बंगाल में भाजपा शासन आया तो लोगों को सरस्वती पूजा करने और दुर्गा मूर्ति विसर्जन की खुली छूट होगी या एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। भद्रलोक ने ही नहीं, आम जनता ने भी इस ब्रांड के हिंदुत्व को पसंद नहीं किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन भाजपा के लिए कुछ आमूल-चूल परिवर्तन का संदेश है। आखिर क्या वजह है कि तीन साल पहले त्रिपुरा चुनाव में जीत के बाद से लगातार इस पार्टी का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन खराब होता जा रहा है? झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली इसके उदाहरण हैं, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां पार्टी शासन में थी, वहां भी स्थिति उत्साहवर्धक नहीं रही। बिहार में उसने जैसे-तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। अगर दो साल पहले बंगाल में लोकसभा चुनाव में पार्टी करीब 120 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त दर्ज कर 18 सीटें जीतती है तो ताजा चुनाव में क्यों वोट डालने गए हर दूसरे वोटर की पसंद ममता बनर्जी बन जाती हैं? हर चुनाव के पहले तथाकथित चुनाव सर्वे की संस्थाएं अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती हैं। उन्हीं के आधार पर हम यह मान बैठते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? बंगाल का उदाहरण लें। अनेक सर्वे में प्रतिशत देकर कहा गया कि तृणमूल कैडर के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और उद्योगों में निवेश न होने से जबरदस्त बेरोजगारी है। यह भी कहा गया कि मोदी की उज्ज्वला योजना की महिलाओं में पैठ है, बिगड़ती कानून-व्यवस्था से महिलाओं में डर है और ममता के मुस्लिम-मोह से हिंदुओं में नाराजगी है, लेकिन शायद भारत में चुनाव सर्वेक्षण के सही होने में अभी कई दशक लगेंगें। सर्वेक्षक हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। बंगाल में कोई नहीं बता पाया कि दस साल के शासन के बाद सत्ताधारी दल लगभग तीन चौथाई सीटें हासिल कर लेगा। तृणमूल के पक्ष में चुनाव परिणाम एक आंधी को बयान करने वाला रहा। राजनीतिशास्त्र में जो लोकमत को प्रभावित करने वाले मुद्दे माने जाते हैं, वे भारत में सही नहीं उतरते। प्रजातंत्र में औसत नागरिकों के मुद्दे समय के साथ बदलते भी हैं। आक्रामक हिंदुत्व का रूप उत्तर प्रदेश और बिहार में जोरशोर से चलता है, क्योंकि वहां क्रमश: 19 और 17 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं और सांप्रदायिक तनाव का इतिहास और वर्तमान भी रहा है। इसकी जरूरत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र आदि में नहीं है। भाजपा बंगाल, केरल तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में उदारवादी हिंदुत्व के जरिये ही पैठ बना सकती है।

गांवों में फैला कोरोना

जहां एक ओर बुरी तरह प्रभावित राज्यों और बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हल्का सुधार दिखने से राहत महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महामारी के गांवों में तेजी से फैलने के संकेत दिख रहे हैं। बिहार, यूपी के जिलों में गंगा और यमुना में सौ से ज्यादा लाशें बहती पाई गई हैं। इस मामले की जांच हो रही है। पता किया जा रहा है कि ये शव आखिर कहां के हैं और इन लोगों की मौत के वास्तविक कारण क्या हैं। लेकिन ऐसी अटकलें लग रही हैं कि कोरोना फैलने से गांवों में मृतकों का अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हो पा रहा और शव नदियों में बहाए जा रहे हैं। गांवों में बड़े पैमाने पर टेस्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, उनमें पॉजिटिव नतीजों का ज्यादा अनुपात बताता है कि संक्रमण स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में यह संभावना मजबूत हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे मामले कोरोना के रूप में चिह्नित नहीं हो पाते होंगे। फिर भी, जो मामले पकड़ में आ रहे हैं, उनके आंकड़े इतना तो स्पष्ट कर ही देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। उदाहरण के लिए 9 अप्रैल से 9 मई के बीच विभिन्न राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बदली स्थिति पर नजर डाली जा सकती है। बिहार में 9 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामले शहरी क्षेत्रों में 47 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 53 फीसदी थे। एक महीने बाद 9 मई को शहरी क्षेत्रों के मामले जहां 24 फीसदी पर आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़कर 76 फीसदी पर पहुंच गए। यूपी में 9 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 49 फीसदी था, जो 9 मई को बढ़कर 65 फीसदी हो गया था। महाराष्ट्र (32 से 56), छत्तीसगढ़ (56 से 89),आंध्रप्रदेश (53 से 72) जैसे अन्य राज्य भी इसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं। यह स्थिति ज्यादा गंभीर इसलिए है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम है, दूसरे वहां लोगों का एक-दूसरे से दूरी बरतना भी सहज नहीं है। ऐसे में एकमात्र उपाय यही बच जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर लोगों में जागरूकता लाने, टेस्ट की संख्या बढ़ाने आइसोलेशन सेंटर खोलने और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का काम तत्काल युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाए। वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में झिझक और कई गलतफमियां भी हैं। इन्हें दूर करने के लिए सरकार को जरूरी अभियान चलाना चाहिए और इन इलाकों में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लानी चाहिए। तभी महामारी को हराने की ओर हम एक बड़ा कदम बढ़ा पाएंगे।

मेडिकल आक्सीजन की किल्लत उत्पादन से कहीं अधिक वितरण तंत्र से जुड़ी

> स्पष्ट है कि आक्सीजन के तात्कालिक संकट की अहम वजह देश में संसाधनों की कमी से कहीं अधिक विपत्ति के समय भी मुनाफे की तिकड़म और कुछ राज्यों की प्रशासनिक अकर्मण्यता है। ये कभी तीन-चार सौ रुपये के पीपीई किट के नाम पर मरीजों से हजारों रुपये वसूलते हैं तो कभी चंद दूरी के लिए एंबुलेंस सेवा के नाम पर लाखों का बिल थमा देते हैं। कोरोना की जंग के साथ मानवता के मूल्यों को कमजोर करने वाले ऐसे विघटनकारी तत्वों से समाज की जागरूकता और सार्वजनिक नियामकों की सख्ती से ही बचा जा सकता है।

आक्सीजन मनुष्य के लिए प्राणवायु है। वातावरण में मौजूद जिस आक्सीजन के जरिये हमारी सांसों की डोर चलती है, उसके लिए हमें न तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं और न ही कतार लगानी पड़ती है। शायद इसीलिए आक्सीजन के प्रति हमने संवेदनशील होना तो दूर, अपनी गतिविधियों से उसकी गुणवत्ता को नष्ट किया। आक्सीजन के चिकित्सकीय रूप ने तो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ही लोगों का ध्यान आर्किषत किया है। आज यह एक ऐसा उत्पाद बन गया है जिसे हासिल करने के लिए मरीज और अस्पताल जिद्दोजहद कर रहे हैं। कई मामलों में तो न्यायालयों को भी दखल देना पड़ रहा है। हालांकि आक्सीजन से जुड़ी यह विपदा संसाधनों के अभाव से कहीं अधिक उसके अनुचित संग्रहण और उसके उपयोग के प्रति जागरूकता के अभाव से उत्पन्न हुई है। औद्योगिक गतिविधियों और चिकित्सकीय उपचार में प्रयुक्त होने वाली आक्सीजन सामान्यत: एक ही संयंत्र में तैयार की जाती है। एक ही प्रकार के टैंक और सिलेंडर के जरिये इसे संग्रहित किया जाता है।

देश में तकरीबन एक लाख टन आक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन होता है। इसमें औद्योगिक और चिकित्सा आक्सीजन, दोनों शामिल हैं। देश में इस्पात उद्योग औद्योगिक उपयोग के लिए आक्सीजन तैयार करता है। इस क्षेत्र के उपक्रम जरूरत पड़ने पर मेडिकल आक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। वहीं निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन में सक्रिय हैं। औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली आक्सीजन की खपत चिकित्सा आक्सीजन के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए इसका परिवहन मुख्य रूप से पाइपलाइन के जरिये ही होता है। अपने देश में आक्सीजन उत्पादन कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है। इनमें कुछ बड़े केंद्र पूर्वी भारत के ओडिशा, झारखंड के अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र की भी आक्सीजन उत्पादन में अच्छी हिस्सेदारी है। इन राज्यों में स्थित संयंत्र औद्योगिक आक्सीजन का पांच से दस प्रतिशत ही लिक्विड रूप में तैयार करते हैं।

अगस्त 2020 में जहां लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन होता था, वहीं आज यह 8,922 मीट्रिक टन उत्पादित की जा रही है। इनमें लगभग 4,500 मीट्रिक टन मेडिकल आक्सीजन स्टील और पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं गंभीर स्थिति में मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति विशेष प्रकार के क्रायोजेनिक टैंकर्स और सिलेंडरों के जरिये ही होती है। ऐसे में देखा जाए तो हमारे यहां मेडिकल आक्सीजन की किल्लत उत्पादन के मोर्चे से कहीं अधिक उसके वितरण तंत्र से जुड़ी है।

मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक और सिलेंडर की कमी ने समस्या को और बढ़ाया है। क्रायोजेनिक टैंक में उन्हीं गैसों को संग्रहित किया जाता है जिन्हें बहुत ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को माइनस185 से लेकर माइनस93 के तापमान में रखा जाता है। इस टैंक के जरिये 20 टन तक आक्सीजन का परिवहन संभव है। क्रायोजेनिक टैंक में दो मजबूत परत होती हैं। दोनों परतों के बीच निर्वात होता है, जिससे बाहर की गरमी का असर भीतर संग्रहित गैस पर बिल्कुल नहीं होता। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास इस समय लगभग 1500 क्रायोजेनिक टैंक हैं। विभिन्न वजहों से 200 टैंक संचालन की स्थिति में नहीं हैं।

हालांकि केंद्र सरकार ने आक्सीजन संकट के सामने आते ही कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। इनका असर दिखने भी लगा है। रेल मंत्रालय, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय तथा राज्यों के परिवहन विभागों का एक उप समूह लगातार आक्सीजन के सुगम परिवहन की निगरानी कर रहा है। वहीं पीएम केयर्स फंड के सहयोग से 162 पीएसए संयंत्र लगाने की योजना संचालन स्तर पर आ चुकी है। ये सभी संयंत्र देश के विभिन्न अस्पतालों में लग रहे हैं। पीएसए संयंत्र सीधे हवा से मेडिकल आक्सीजन तैयार करने की तकनीक पर काम करते हैं। सरकार ने आक्सीजन संकट के शुरुआती दिनों में ही इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध सरप्लस स्टॉक के उपयोग की अनुमति दे दी थी। सरकार आक्सीजन स्नोतों के लिए राज्यों की मैपिंग भी कर रही है। इस प्रक्रिया से आक्सीजन की उपलब्धता वाले स्नोत से निकटवर्ती मांग वाले राज्यों को सुगम आपूर्ति का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में औद्योगिक सिलेंडरों को भी मेडिकल आक्सीजन के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने की अनुमति दी गई है।

वैक्सीन मैत्री का प्रतिफल आक्सीजन संकट के दौर में वैश्विक सहयोग के रूप में भी देखने को मिल रहा है। अब तक दर्जन भर से अधिक देशों से आक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति की जा चुकी है। चूंकि देश में मेडिकल आक्सीजन की आर्पूित में एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, इसलिए यदि सरकार निजी क्षेत्र की गैस कंपनियों की क्षमता का पूरा लाभ लेना चाहती है तो उन्हें र्आिथक पैकेज या सहयोग प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि आक्सीजन के तात्कालिक संकट की अहम वजह देश में संसाधनों की कमी से कहीं अधिक विपत्ति के समय भी मुनाफे की तिकड़म और कुछ राज्यों की प्रशासनिक अकर्मण्यता है। ये कभी तीन-चार सौ रुपये के पीपीई किट के नाम पर मरीजों से हजारों रुपये वसूलते हैं तो कभी चंद दूरी के लिए एंबुलेंस सेवा के नाम पर लाखों का बिल थमा देते हैं। कोरोना की जंग के साथ मानवता के मूल्यों को कमजोर करने वाले ऐसे विघटनकारी तत्वों से समाज की जागरूकता और सार्वजनिक नियामकों की सख्ती से ही बचा जा सकता है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

बहराइच में यूपी 112 की टीम पर जानलेवा हमला, दारोगा के सिर पर गंभीर चोट; होमगार्ड का टूटा अंगूठा

बहराइच । हरदी थाना क्षेत्र के बरोलिया गांव में लड़ाई, झगड़े की सूचना पर पहुंचे यूपी 112 के दारोगा व होमगार्ड पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें दारोगा के सिर में गंभीर चोटें आई जबकि होमगार्ड का अंगूठा टूट गया। मामले में 16 लोगों पर जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष आरपी यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के बरोलिया गांव निवासी सगे भाई मालती, भगवती व पारसनाथ जमीन को लेकर आपस में मारपीट पर आमाद थे। तीनों लोगों की ओर से भीड़ एकत्रित होने लगी। मालती की पत्नी मीरा ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही क्षेत्र में मौजूद यूपी 122 के दारोगा संतोष कुमार बाजपेई होमगार्ड पंकज तिवारी के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने दोनो पक्षो को गाड़ी पर बैठाकर थाने ले जाने लगे। आरोप है कि इस दौरान गाड़ी में बैठा वासुदेव वाहन से कूदकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोप है कि वासुदेव को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में दारोगा व होमगार्ड को गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी दारोगा ने जैसे ही वायरलेस सेट पर प्रसारित की तो पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख में पुलिस बल लेकर पहुंचे थानाध्यक्ष ने भीड़ के चंगुल से पुलिसकर्मियों को छुड़ाया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में दारोगा संतोष वाजपेयी की तहरीर पर पारसनाथ, मालती, वासुदेव, दुर्गा, भगवती व सर्वेश समेत 16 लोगों पर बलवा, जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य मे बाधा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल दरोगा को उपचार के लिए सीएचसी महसी भेजा गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से पुलिस ने कराई उठक-बैठक, बक्सर में दारोगा पर केस दर्ज कराने के लिए अड़े

बक्सर । बक्सर जिले में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को लॉकडाउन तोड़ने पर ऑन द स्पॉट सजा देने वाली पुलिस मुश्किल में पड़ गई है। नेताजी अब संबंधित दारोगा पर मुकदमा दर्ज करने पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि परिचय देने के बाद भी पुलिस ने उनकी कद्र नहीं की और दारोगा ने सार्वजनिक जगह पर उनसे उठक-बैठक कराई। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार राम ने अनुसूचित जाति- जनजाति थाने में आवेदन देकर दारोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है।

कलेक्ट्रेट रोड स्थित कार्यालय से लौटने के दौरान हुई घटना- अनिल का कहना है कि, वह शनिवार की शाम तकरीबन 6:30 बजे समाहरणालय रोड स्थित पार्टी कार्यालय से निकलकर ज्योति प्रकाश चौक की तरफ दवा लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह अंबेडकर चौक पर पहुंचे, नगर थाने में पदस्थापित एसआई सुभाष चंद्र प्रसाद ने उन्हें रोका और मास्क नहीं पहने होने के कारण उनसे उठक-बैठक कराई। इतना ही नहीं उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालियां भी दी जबकि, अनिल ने उन्हें यह बताया था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा दवा लेने के लिए जा रहे हैं।

कई अधिकारियों को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार- अनिल ने कहा कि अपना परिचय देने के बावजूद एस.आई. के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई जबकि, उन्होंने स्वयं मास्क नहीं पहना था। ऐसे में उन्होंने मामले को लेकर दारोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है। मामले को लेकर उन्होंने बिहार सरकार के पुलिस महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र के पुलिस उप निरीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन की प्रति भेज न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल यह पूरा प्रकरण वैसे लोगों के लिए सबक है, जो लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर निकल कर घूमना अपनी शान समझ रहे हैं।

60 किलो गांजा के साथ तीन गिरफ्तार, छह लाख से अधिक नगदी बरामद

कल्याणपुर (समस्तीपुर) । दरभंगा में गिरफ्तार गांजा तस्करों से पूछताछ के क्रम में मिली जानकारी के आधार पर दरभंगा के बिशनपुर थाना व हायाघाट थाना द्वारा संयुक्त रुप से कल्याणपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। कल्याणपुर के जटमलपुर स्थित महादेव स्थान चौक के पास एक मकान पर छापेमारी की गई। जहां से पुलिस ने छह लाख पंद्रह हजार रुपये नगद के साथ गांजा भी बरामद किया। पुलिस ने खगड़िया जिले के अलौली थाना के हरिनारायण यादव उर्फ हीरा यादव,कल्याणपुर थाने के मनकौली के मो. कलाम व जटमलपुर के सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पूछताछ के लिए हायाघाट लेते चली गई। कल्याणपुर के प्रभारी थाना अध्यक्ष टुन्नानंद झखड़ ने बताया कि थाना को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है। तस्करों के पास से 60 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। जिसका बाजार मूल्य 40 लाख रुपये बताया जा रहा है। दरभंगा एसपी बाबूराम ने बताया कि हायाघाट पुलिस व टेक्निकल टीम के मदद से रविवार की रात हायाघाट व कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तीन लोगों को 60 किलो गांजा , छह लाख पंद्रह हजार रूपये ,बाइक, साइकिल, मोबाइल आदि सामान बरामद की गई है। गिरफ्तार तीन लोगों में दो कल्याणपुर थाना के हैं। वही एक खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र का है। तीनों से पूछताछ की जा रही है।

तेजस्वी यादव ने सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा- बिहार सरकार का स्वास्थ्य महकमा आइसीयू में पहुंच,

पटना । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2019-2020) की रिपोर्ट के हवाले से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा आइसीयू में है।

राजद शासनकाल को बताया सुदृढ़- तेजस्वी ने कहा कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद राज्य सरकार की समझ में आ जाना चाहिए कि 2005 में राजद शासनकाल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी और 16 वर्ष बाद नीतीश-भाजपा राज में कितनी जर्जर है सन् 2005 में ग्रामीण बिहार में 10337 कार्यरत स्वास्थ्य उप केंद्र थे, जबकि 2020 में कागजों में केवल 9112 उप केंद्र हैं। उनमें से अधिसंख्य कार्यरत भी नहीं हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या घटी

तेजस्वी ने कहा कि 2005 में प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या 101 थी, जो 2020 में घटकर केवल 57 रह गई है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि 16 वर्षों में प्रदेश में 2005 तक कार्यरत कितने स्वास्थ्य केंद्रों को उसने कब, क्यों और किसलिए बंद कराया डेढ़ दशक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य उप केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रोंकी संख्या बढ़ाने के बजाय नीतीश सरकार द्वारा कम कर दी गई

झारखंड के रसोईया सह सहायिकाओं के मानदेय में रुपये500 का इजाफा, अब प्रतिमाह मिलेंगे दो हजार रुपये

रांची । मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोईया सह सहायिकाओं के लिए राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में पांच सौ रुपये का इजाफा किया गया है। अब इन्हें मानदेय के रूप में प्रतिमाह दो हजार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया-सह-सहायिकाओं को राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर 39.78 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दे दी है। यह राशि वार्षिक दस माह के लिए है।

बता दें कि केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक रसोईया-सह-सहायिका को एक हजार रुपये मानदेय देने का प्रविधान है। इसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का अंशदान करती है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इन्हें हर माह अतिरिक्त पांच सौ रुपए जोड़कर देती आ रही है। इस राशि में अब पांच सौ रुपये की बढ़ोत्तरी कर एक हजार रुपये कर दिया गया है। इस तरह सभी रसोईयों-सह-सहायिकाओं को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 79,591 रसोईया-सह-सहायिका को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़त पर रिकवरी रेट, 24 घंटे में 3981 नए संक्रमित

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रिपल टी (टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट) मॉडल के साथ ही मंडल व जिलों के स्थलीय निरीक्षण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। एक माह से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के कारण ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का रिकवरी रेट अब 94.30 प्रतिशत पर आ गया है। बीते 23 घंटे में 3981 नए संक्रमित मिले हैं जबकि तीन लाख 17684 सैंपल का टेस्ट किया गया।

उत्तर प्रदेश ने देश में एक दिन में सर्वाधिक टेस्टिंग (3,26399 लाख) का रिकॉर्ड बनाया है। इस टेस्ट की बढ़ती संख्या के बावजूद प्रदेश सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में अब 75 में से 49 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केस संख्या घटकर हजार से नीचे आ गयी है। बीस जिले ऐसे हैं जहां पर सक्रिय केस 500 से भी कम है। सूबे की राजधानी लखनऊ में जहां 24 घंटे में छह हजार से नए मामले आते थे, अब एक्टिव केस की संख्या 5458 है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 3,981 मामले सामने आए और 11,918 लोग डिस्चार्ज हुए। अब 76,703 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में 157 लोगों की मृत्यु हुई। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि हर अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अब हमारे कई अस्पतालों और रिफिलिंग सेंटर के पास बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। भविष्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए 450 से अधिक प्लांट प्रदेश में लगाए जा रहे हैं।

24 घंटे में 3981 नए संक्रमितः प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3981 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इसके संक्रमण से 11918 लोग उबरे हैं। अब प्रदेश में कोरोना वायरस के 76703 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 326399 कोरोना टेस्ट हुए हैं। यह एक दिन में सर्वाधिक टेस्ट का देश में रिकार्ड है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण मामले घटकर 3981आ गए। बीती 24 अप्रैल को यह संख्या 38055 थी। अब सक्रिय मामले 76703 हैं, जो कि 30 अप्रैल को 310783 के रिकॉर्ड स्तर पर थे।

10 जिलों में केस दहाई पर सिमट गए- प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी के बीच में अब नए संक्रमण 3981 पर सिमट रह हैं। 24 घंटे में सर्वाधिक संक्रमण वाले जिलों में सहारनपुर में 323, मेरठ में 296, लखनऊ में 215 व बुलंदशहर में 195 नए केस सामने आए हैं। कौशांबी में तो 24 घंटे में एक भी केस नहीं। अब 10 जिलों में केस दहाई पर सिमट गए हैं। हमीरपुर, कानपुर देहात, हाथरस, महोबा, बांदा, औरैया, फतेहपुर, चित्रकूट, मीरजापुर तथा जालौन में नए संक्रमण के मामले इकाई में ही सिमटे रहे। प्रदेश में पॉजिटिविटी 17 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत पर आ गई है। बीते 17 दिनों में 21 मई को छोड़ दें तो प्रदेश में संक्रमण के घटने का लगातार 16 वां दिन है।

मिशन मोड में कामः सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद मिशन मोड में काम करने अब और शहर से लेकर गांव तक कोरोना संक्रमण में कुछ नियंत्रण लगा है। मुख्यमंत्री ने सभी को काम की प्राथमिकता तय करने के साथ प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मोर्चे पर लगाया। कोरोना से खुद संक्रमित होने के बावजूद रोज बैठक में मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समाज के अलग वर्ग लोगों से ऑनलाइन संवाद बनाए रखा। संक्रमण से निगेटिव होने के बाद से ही अपने निदेशों के भौतिक सत्यापन के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं।

बिहार में अब 1 जून तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने कईं महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं

पटना । बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन को 25 मई के बाद भी जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि एक जून तक विस्तार किए जाने का फैसला लिया। मालूम हो कि 25 मई को लॉकडाउन-2 की अवधि समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का आधार यह रहा कि इससे कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आयी है। पहले तीन सप्ताह तक लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आए हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारियों से दो दिनों तक लिया गया था फीडबैक- मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दिनों तक लगातार सभी जिलाधिकारियों से लॉकडाउन पर अधिकारियों ने फीडबैक लिया था। सभी लोगों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के सुझाव दिए। सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का निर्णय हुआ। अब लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत पहले की तरह ही सभी डीएम व एसपी को कोरोनावायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

कोरोना जांच की संख्या को और बढ़ाएंगे- मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जांच की संख्या को और बढ़ाना है। अभी प्रतिदिन 1.27 लाख जांच हो रही है। इसे प्रतिदिन 1.50 लाख तक ले जाना है। मार्च महीने में दस लाख की आबादी पर देश में प्रतिदिन जितनी जांच हो रही थी, उसकी तुलना में बिहार में 14 हजार जांच अधिक हो रही थी। चलंत टेस्टिंग वैन की शुरुआत की गयी है, जिससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार जांच होगी तथा जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी।

कोरोना से मरे लोगों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं- मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी भी मृत्यु हुई है उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करें और परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों के टीकाकरण के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में तय हुई गाइडलाइन- सोमवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन-3 की गाइडलाइन पर अंतिम फैसला लिया गया। इसके पहले रविवार को मुख्य सचिव ने गृह, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात और लॉकडाउन को लेकर विचार-विमर्श किया। कई विभागों ने लॉकडाउन लागू रखने के पक्ष में राय दी। कई अधिकारियों ने पांच जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी। जिलाधिकारियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय दी। सबकी राय लेने के बाद सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई थी। इसके पहले मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को एक सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

एक जून तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद- विदित हो कि राज्य में अप्रैल से मई के बीच कोरोनावायरस संक्रमण के मामले काफी बढ़े। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद पांच मई से लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी मियाद 15 मई तक थी। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई। कम होते मामलों को देखते हुए दूसरी बार 13 मई को लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर सहमति बनी। उसके बाद 16 मई से लॉकडाउन-2 लागू किया गया। लॉकडाउन में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन की मियाद को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। इसे देखते हुए आज एक जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद- आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार मौजूद थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार व मुख्यमंत्री के सचिव अनुप कुमार भी जुड़े थे।

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने एडीए को सौंपा नक्शा, अयोध्या के धन्नीपुर में होगा मस्जिद का निर्माण

अयोध्या । इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने सोहावल तहसील के धन्नीपुर राजस्व ग्राम में अपनी प्रस्तावित मस्जिद की ड्राइंग 11 सेट में सोमवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल झखड़ को सौंप दी। रामजन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील के धन्नीपुर राजस्व ग्राम में पांच एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष के अनुसार ऑफ लाइन नक्शा आवेदन को अनुमोदन के लिए शासन भेजा जा रहा है। शासन से अनुमोदन के बाद ही मानचित्र स्वीकृति का शुल्क तय होगा। प्राधिकरण में नक्शा मंजूरी के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन आवेदन संभव न हो पाने से ट्रस्ट ने ऑफलाइन आवेदन किया है। अनुमोदन के लिए इसीलिए शासन भेजा जा रहा है।

ट्रस्ट कैप्टन अफजाल अहमद खान के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस 89 हजार रुपये भी जमा कर दी गयी है। मस्जिद का नक्शा बड़ा होने के कारण ऑनलाइन आवेदन संभव न होने से ट्रस्ट ने ऑफलाइन आवेदन किया है। आयकर विभाग से अभी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को 80 जी का टैक्स छूट प्रमाणपत्र जारी न किए जाने पर ट्रस्टी अफजाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

ये होगी व्यवस्था - इसमें 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोजाना लगभग एक हजार लोगों को खिलाएगी, एक अनुसंधान केंद्र जो समर्पित है महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम और एक मस्जिद जो एक बार में दो हजार नमाजियों को समायोजित कर सकती है शामिल है। उन्होंने बताया कि ग्यारह सेटों में नक्शे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंपे गए हैं। ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89 हजार रुपये भी जमा करा दिए हैं।

ट्रस्ट कैप्टन अफजाल ने बताया कि परियोजना का नक्शा आकार में बड़ा है और सामान्य मानचित्रों से बहुत अलग है इसलिए इसे ऑनलाइन एप्लाई नहीं किया जा सका है, इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण से मानचित्र को ऑफलाइन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। कैप्टन अफजाल ने आयकर विभाग द्वारा इंडो इस्लामिक कल्चरल फ़ाउंडेशन को 80जी का टैक्स छूट प्रमाणपत्र जारी न करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है, उन्होंने बताया इसके कारण ट्रस्ट के लिए दान रुका हुआ है और यह हमारी परियोजना को शुरू करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

नालंदा में प्रेमिका से मिलने आया था युवक, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर करा दी शादी

चंडी (नालंदा)। स्थानीय थाना क्षेत्र के गौड़ापर गांव में शनिवार रात प्रेमिका से मिलने आये युवक को पकड़ कर चंडी माता मंदिर परिसर में बने शिवालय में शादी करा दी गई। लड़की के पिता ने समाज के लोगों से मशविरा करने के बाद इस अंतरजातीय विवाह पर रजामंदी दे दी। शादी करवाने में थाना पुलिस ने भी मदद की। लड़की पिछड़ी जाति तथा लड़का अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस शादी की चर्चा हर लोगों की जुबां पर है।

लड़की ने चुपके से प्रेमी को बुलाया - शनिवार रात लड़की के पिता व घर के अन्य सदस्य किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसका फायदा उठा लड़की ने अपने प्रेमी प्रिंस कुमार को घर में बुला ली। पड़ोसियों को भी इस प्रेम संबंध की खबर थी। पड़ोस के कुछ लोगों को जैसे ही प्रेमी जोड़ी को घर में मौजूदगी की भनक लगी, घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बन्द कर दिया। लड़की के पिता को मोबाइल फोन पर इसकी जानकारी दे दी।

कमरे में बंद मिले प्रेमी युगल- लड़की के स्वजन आये तो प्रेमी युगल को कमरे में बन्द पाए। थाना पुलिस को इसकी खबर दी गई। स्थानीय चौकीदार ने मामले की पूरी जानकारी थानाध्यक्ष को दी। लड़की के पिता ने गांव के कुछ लोगों से इस मामले में सलाह लिए। तय हुआ कि कोई और कदम उठाने से अच्छा है कि दोनों की शादी करा दी जाए। प्रेमी युगल को माँ चण्डिका मंदिर ले जाया गया। वहां शिवालय के समक्ष देवी-देवताओं को साक्षी मान लड़के ने प्रेमिका की मांग भर कर उसे पत्नी के तौर पर स्वीकार किया और अपने साथ ले गया। लड़की के पिता चंडी के डाकबंगला रोड में स्टेशनरी की दुकान है। लड़का मानपुर थाना क्षेत्र के भंवरा पर निवासी झुन्नू चौधरी के पुत्र है। वह नूरसराय के यहिया पुर में अपने नाना महेंद्र चौधरी के यहां रहता था। नूरसराय में दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के वक्त लड़का के मामा शिव शंकर कुमार मौजूद थे।

आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक, हेलिकॉप्टर की लैंडिंग के समय पहुंची गाय

आजमगढ़ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा तथा गांव का निरीक्षण करने के बाद हेलिकॉप्टर से आजमगढ़ रवाना हुए। आजमगढ़ में उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। यहां पर पुलिस लाइन में जब हेलिकॉप्टर लैंड हो रहा था, तभी हैलीपैड के पास एक गाय आ गई। बाद में पुलिसकर्मियों ने उसको भगाया। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड की समीक्षा करने के बाद वाराणसी रवाना हो गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ दौरे में आज सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। यहां उनके हेलीकॉप्टर के उतरने समय उसके नजदीक गाय दौड़ पड़ी। कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको दूसरी तरफ भगाया तब, सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलिकॉप्टर की सही सलामत लैंडिंग हो सकी। करीब दो बजे आजमगढ़ पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता कि वहां पर कहीं से एक गाय पहुंच गई। वहां पर उड़ती धूल के बीच में भी सुरक्षाकर्मियों ने उस गाय को हेलीपैड की ओर जाने से रोक दिया।

यहां पर लैंड करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर रवाना हो गए। उनके साथ में फूलपुर से भाजपा विधायक अरुणकांत यादव, बलिया से एमएलसी विजय बहादुर पाठक तथा भाजपा जिलाध्यक्ष सहित मौजूद थे।

सीएम बोले- वैक्सीन लगवाने से कोई भी परहेज न करें : आजमगढ़ दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा तथा निरीक्षण के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी से मेरी अपील है कि आप सब लोगों को इस महामारी के प्रति हर स्तर पर जागरूक करें। कोई भी इसका टेस्ट कराने और वैक्सीन लगवाने से परहेज न करें। वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर कोरोना महामारी से बचने का सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्यवाही को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। एक जून से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होगी और हम सभी 75 जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को विस्तार देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर काफी हद तक पर काबू पा लिया गया है। यह जब आई थी तब आशंका जताई गई थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा मामले आएंगे। उत्तर प्रदेश ने इस आशंका को निर्मूल साबित किया है। साफ है कि प्रदेश में संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाया गया है। इसमें शासन, प्रशासन, जन प्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वरियर व जनता जनार्दन का सहयोग रहा है। हम सेकंड वेव को 31 मई तक काफी हद तक काबू कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की आई जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में करीब 15 प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय व सीएससी शामिल है। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को उन्होंने थर्डवेव के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया।

यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई को कैसे मिली नियुक्ति, राजभवन ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से किया जवाब तलब

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी के भाई डॉ. अरुण कुमार द्विवेदी की अल्प आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हुई नियुक्ति पर अब राजभवन ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जवाब तलब कर लिया है। पूरे विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सोमवार को राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी के भाई डॉ. अरुण कुमार की नियुक्ति सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में मनोविज्ञान विभाग में हुई है। लेकिन, इनकी नियुक्ति अब विवादों के घेरे में आ गई है, जिसके बाद से लगातार जांच की मांग की जा रही है। अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने भी जांच की मांग की है। नूतन का कहना है कि डॉ अरुण की नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे से हुई है। उन्होंने कहा कि डॉ अरुण वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में भी प्रोफेसर थे। साथ ही वह शिक्षा मंत्री के भाई भी हैं। ऐसे में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए गरीबी के प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े होते हैं। नूतन ठाकुर ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस संबंध में साक्ष्यों के साथ पत्र लिखा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पूरे मामले में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेंद्र दुबे का कहना था कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति हुई है। प्रमाणपत्र फर्जी होगा तो नियुक्ति निरस्त की जाएगी, जबकि सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने अरुण के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को सही ठहराया है। इटावा के तहसीलदार अरविंद कुमार के अनुसार, सामान्य वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम हो, शहरी क्षेत्र में उसका 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल का मकान न हो और उसके नाम पांच एकड़ से कम जमीन हो तो उसे ईडब्ल्यूएस कोटे में प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। वहीं अब इस मामले में राजभवन ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब कर लिया है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट से विधायक हैं। उनके भाई का चयन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। 21 मई को अरुण के विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हो रहे हैं। मामला राजभवन तक पहुंच गया है। इधर, सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा ने कहा कि अरुण द्विवेदी सभी पात्रता पूरी कर रहे थे। जिस समय अरुण का प्रमाणपत्र बना था, वह वनस्थली की नौकरी छोड़ चुके थे। जांच के बाद पात्रता मिलने पर ही प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो पर सियासत जारी, मांझी बोले-डेथ सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं दे रहे तस्वीर

पटना । कांग्रेस शासित राज्यों के बाद अब एनडीए की साझा सरकार के एक पार्टनर ने भी कोरोना वैक्सीन के डिजिटल सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जाहिर की है। बिहार में एनडीए सरकार में शामिल हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री के फोटो का विरोध किया है। माना जा रहा है कि मामले में मांझी अपने मोर्चे के अलावा जदयू के नेताओं की भावना का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक अन्य सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि भाजपा ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

मांझी ने क्या कहा है- मांझी ने कहा था कि को-वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संविधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं। इस नाते प्रमाण पत्र में राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी हो तो राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर हो। मांझी इतने पर ही नहीं रूके। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए। यही न्याय संगत होगा।

फ्री थिंकर्स श्रेणी में हैं पूर्व मुख्यमंत्री - 76 साल के बुजुर्ग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को फ्री थिंकर्स श्रेणी में रखा जाता है। वे कब किसी का विरोध करेंगे, कब उसी का समर्थन कर देंगे, उनके पास इसका हिसाब-किताब नहीं रहता है। हाल के दिनों में वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में मुस्तैदी से खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनके निशाने पर मुख्य विपक्षी दल राजद आ गया था। राजनीतिक मोर्चे पर उनकी पुत्रवधु दीपा संतोष मांझी भी साथ दे रही हैं। दीपा मुख्य रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य से ट्वीटर वार कर रही हैं।

क्या कह रही है भाजपा- भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने मांझी के ट्वीट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा-वह नहीं जानते कि सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनकी सहमति से दी जा रही है। लेकिन, वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री ने देश और विदेश के मंचों पर जितना प्रयास किया, वह अभूतपूर्व है। ऐसी हालत में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर न देना, उनके प्रति अन्याय होगा। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री की तस्वीर देखने से आम लोगों का विश्वास जगता है।

कोलकाता में कोविड रोगियों के लिए खालसा इंग्लिश हाई स्कूल में ऑक्सीजन पार्लर के उद्घाटन के दौरान टीएमसी सांसद माला रॉय और पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री सोवन्देब चटोपाध्याय।

ब्यावर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद एक युवा जोडा सेल्फी लेते हुए।

हैदराबाद के सरोजिनी देवी आई अस्पताल में डॉक्टरों ने म्यूकोर्मिकोसिस से संक्रमित होने वाले मरीजों की आंखों की जांच करते हुए।

एक नजर

पांच साल पहले हो चुकी मृत दंपती के नाम पर श्रीगंगानगर में लगा कोविड वैक्सीन

उदयपुर । कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जिस दंपती के नाम श्रीगंगानगर में पिछले दिनों टीकाकरण हुआ, उनकी मौत पांच साल पहले हो चुकी है। ऐसे में आधार कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। डूंगरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि जिले के फौज का बड़ला गांव के दिवंगत दंपती रमेश चंद्र गांधी और उनकी पत्नी के नाम श्रीगंगानगर जिले में टीकाकरण की जानकारी मिली है। जबकि रमेश चंद्र गांधी का निधन साल 2014 में जगकि उनकी पत्नी इंदिरा देवी का निधन साल 2015 में हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार के किसी सदस्य का श्रीगंगानगर जिले में कोई लिंक नहीं है और ना ही उनका कोई परिचित। दिवंगत रमेश चंद्र के बेटे प्रवीण ने वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र डाउनलोड कराकर जांच की मांग की है। इस मामले में सीएमएचओ डॉ. शर्मा का कहना है कि ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि किसी ने दस्तावेजों का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई है।

विधायक ने की शिकायत, सप्ताह में एक ही दिन आते हैं डॉक्टर- डूंगरपुर जिले के चौरासी विधायक राजकुमार रोत ने चिक्तिसा विभाग को शिकायत की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुराता में नियुक्त चिकित्सक डॉ. अनिल जायसवाल सप्ताह में केवल एक ही दिन अस्पताल आते हैं। उन्होंने रविवार को अस्पताल का जायजा लिया तो वहां डॉक्टर जायसवाल नहीं मिले, जबकि रजिस्टर में उन्होंने एडवांस में हस्ताक्षर कर रखे थे। यही नहीं फर्जी मरीजों के नाम भी मरीजों के पंजीयन रजिस्टर में अंकित थे। उन्होंने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा से मौके से बात की तथा कार्रवाई करने को कहा।

पांचवीं पास भाजपा विधायक मरीज को इंजेक्शन देते नजर आए, कांग्रेस ने कसा तंज

अहमदाबाद । गुजरात के सूरत में भाजपा विधायक वीडी झालावाडिया कोविड केयर सेंटर में मरीज की ड्रिप में इंजेक्शन देते नजर आए तो हंगामा मच गया। इंटरनेट मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद विधायक ने माफी मांगते हुए कहा कि वह सेवा कर रहे हैं, किसी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते। सूरत के कामरेज से विधायक वीडी झालावाडिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज की ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ वहां चिकित्सक व नर्स भी मौजूद हैं। इंटरनेट मीडिया पर लोग विधायक को खूब-खरी खोटी सूना रहे हैं। विवाद बढ़ा तो विधायक ने माफी मांगते हुए कहा कि वे 40 दिन से केयर सेंटर चला रहे हैं तथा यहां अब तक 200 लोगों का उपचार हो चुका है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तथा वे कोई विवाद भी खड़ा नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि झालावाडिया महज पांचवीं पास हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा कि राज्य में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को ऐसे पांचवीं पास नेताओं की सेवाएं लेनी चाहिए। राज्य में कोविड सेंटर बनाकर अपने ऐसे नेताओं को उपचार के लिए सौंप देना चाहिए। नवंबर 2020 में भी झालावाडिया अपने पौत्र के जन्म दिन पर कोरोना महामारी की मार्गदर्शिका की धज्जियां उड़ाते नजर आ चुके हैं। उनके पुत्र शरद भी दो साल पहले धमकी के दो मामलों में सुर्खियां बटोर चुके हैं। इंटरनेट मीडिया में झालावाडिया को मुन्नाभाई एमबीबीएस को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों की जान से खेलना बंद करो।

गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर हो आईसीयू मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य यही है की एक डॉक्टर व कुछ पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर एक पूरे अस्पताल को चला सकें। उधर, कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं नेता विपक्ष परेश धनानी विविध जिलों के सरकारी अस्पतालों में घूम कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी तथा डीआरडीओ ने मिलकर हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक सप्ताह का आईसीयू मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के 30 डॉक्टर कथा बीजे मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ गुजरात विश्वविद्यालय में हेल्थ केयर वर्कर को अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के संचालन तथा कोरोना के संकटकाल में मरीजों की कैसे देखभाल की जाए इसका प्रशिक्षण देंगे।

गुजरात में चक्रवात ने मचायी भयंकर तबाही, आम की पैदावार पूरी तरह चौपट

अहमदाबाद । अरब सागर से उठे अति तीव्र चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचाई जिसके कारण सबसे अधिक कृषि एवं फलों के बागों को नुकसान हुआ। आम के बड़े-बड़े पेड़ इस तूफान में उखड़ गए तथा लोगों की 20- 20 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। एक अनुमान के मुताबिक आम पैदावार करने वाले लोगों को सौराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। फलों का राजा आम मैं भी लोगों को सबसे अधिक प्रिय केसर आम की सबसे अधिक पैदावार सोमनाथ, अमरेली और जूनागढ़ में होती है।

इन जिलों में आम की पैदावार चौपट - चक्रवात का सबसे अधिक असर भी इन जिलों पर ही रहा जिसके कारण अब इन जिलों में आम की पैदावार पूरी तरह चौपट हो गई तथा बाग लगाने वाले अब तूफान के कारण गिरे आमों को जानवरों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। आम के अलावा चीकू, नारियल, केले के पेड़ों को भी भारी नुकसान हुआ है। गेहूं तथा कपास में मूंगफली के फसलों में भी भारी बर्बादी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि किसानों पशु पालकों एवं बागायती खेती करने वाले लोगों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सरकार ने इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है तथा जल्द ही नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।

किसान मनु भाई महेश भाई पटेल बताते हैं कि सौराष्ट्र में आम की फसल तूफान एवं बारिश के कारण पूरी तरह खराब हो चुकी है। जो आप पेड़ से उतारकर पेटियों में भरे गए थे बारिश में भीगने के कारण वह भी खराब हो गया। मंडी में जिस आम का भाव 900 से 1200 पेटी था उसे अभी 200 से 300 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बागायती खेती करने वालों को अब अपने फल या तो सड़क पर फेंक रहे हैं या जानवरों को खिला रहे हैं।

गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू, हेल्थकेयर वर्कर को खास ट्रेनिंग

अहमदाबाद । कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर हो आईसीयू मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य यही है की एक डॉक्टर व कुछ पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर एक पूरे अस्पताल को चला सकें। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं नेता विपक्ष परेश धनानी विविध जिलों के सरकारी अस्पतालों में घूम कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी तथा डीआरडीओ ने मिलकर हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक सप्ताह का आईसीयू मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के 30 डॉक्टर कथा बीजे मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ गुजरात विश्वविद्यालय में हेल्थ केयर वर्कर को अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के संचालन तथा कोरोना के संकटकाल में मरीजों की कैसे देखभाल की जाए इसका प्रशिक्षण देंगे।

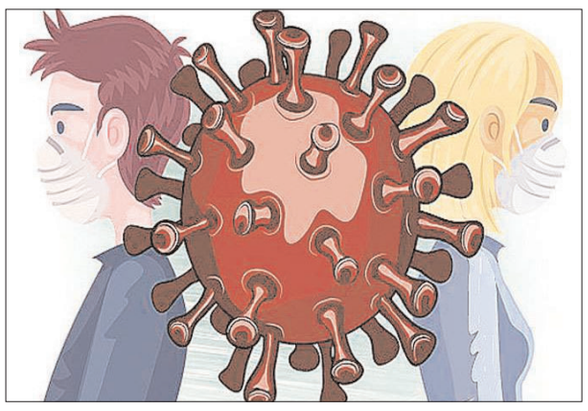

गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ हिमांशु पंड्या ने बताया कि चिकित्सक मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा इस पाठ्यक्रम के जरिए चिकित्सकों को पैरामेडिकल स्टाफ को ऐसा तैयार किया जाऐगा कि पूरे कोविड हॉस्पिटल को संचालित कर सकें। बीजे मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कमलेश उपाध्याय ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चिकित्सकों एवं मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने से पहले उससे निपटने की बारीकियां सिखाना है।

एक चिकित्सक कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर किस तरह कोविड-19 हॉस्पिटल तथा आईसीयू को चला सकता है इसकी ट्रेनिंग देना पहला उद्देश्य है। गुजरात कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में आग की घटनाओं तथा इंजेक्शन व अन्य मेडिकल साधनों की कालाबाजारी को लेकर लगातार सरकार पर हमले कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और नेता विपक्ष परेश धनाणी जहां विविध जिलों के सरकारी अस्पतालों में घूम कर स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके उपचार की जानकारी ले रहे हैं वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को पत्र लिखकर म्यूकर माइकोसिस बीमारी से ग्रस्त लोगों का सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में इलाज करने की मांग की है।

हार्दिक ने कहा है कि कोरोना के इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी के मामले सामने आए अब म्यूकर माइकोसिस से इंजेक्शन को लेकर भी पीड़ितों के परिजनों को परेशानी हो रही है।

सरकार जमाखोरों एवं कालाबाजारी उसे नहीं निपट पा रही इसलिए सरकारी के अलावा गैर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेजों में भी म्यूकर माइकोसिस का उपचार निशुल्क घोषित कर देना चाहिए। सरकार ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल सहित विभिन्न शहरों के 7 अस्पतालों से म्यूकर माइकोसिस के इंजेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ताकि पीड़ितों के परिजनों को कालाबाजारी से बचाया जा सके। सरकार ने कहा है कि इंजेक्शन पीड़ित के परिजनों के बजाय अब सीधे अस्पताल को ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

वेंटिलेटर पर महिला, बच्चे को दिया जन्म

अजमेर । राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती एक कोरोना पीड़ित महिला ने स्वस्थ बच्चे का जन्म दिया। मां चिकित्सकों की निगरानी में वेंटिलेटर पर है। बच्चे को एनआइसीयू में रखा गया है। जेएलएन चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अनिल जैन ने बताया कि चिकित्सालय में पिछले दिनों खानपुरा अजमेर निवासी 29 वर्षीय गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव भर्ती हुई। महिला की श्वास की गति ज्यादा और ऑक्सीजन लेवल 74 प्रतिशत पर होने पर उसे ट्रोमा आइसीयू मे वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया गया। इसी बीच, महिला के प्रसव पीड़ा होने पर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशन कर बच्चे को बचाने का फैसला लिया। महिला को ऑक्सीजन व वेंटिलेटर सहित ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। डॉ. मैना सिंह के मार्गदर्शन मे डॉ. कृति, डॉ. सुनील, डॉ. विदिशा, डॉ प्रेम व डॉ. गोपाल ने सफलता पूर्वक जटिल इमरजेंसी ऑपरेशन किया। इसमें कमलेश,

पिंकी एवं अशोक ने ऑपरेशन मे सहयोग दिया। कोविड वेंटिलेटर नोडल ऑफिसर डॉ. अरविन्द खरे ने बताया कि ऑपरेशन के बाद शिशु स्वस्थ है, उसे एनआइसीयू में निगरानी पर रखा गया है। महिला को आइसीयू मे वेंटिलेटर पर रखा हुआ है।

जिला मुख्यालय में 197 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध - जिला मुख्यालय में कोरोना मरीजों के लिए उपचाररत चिकित्सालयों में 197 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध है। चिकित्सालयों में से बीते 48 घंटों में 50 मरीज डिस्चार्ज हुए। जेएलएन चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. अनिल जैन ने बताया कि जिला मुख्यालय पर तीन कोविड डेडीकेड चिकित्सालयों में कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जेएलएन चिकित्सालय, राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर तथा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील में कोरोना मरीजों के लिए रविवार को 197 बेड उपलब्ध रहे। जेएलएन चिकित्सालय में 160, सैटेलाइट चिकित्सालय में 12 तथा पंचशील अरबन सीएचसी में 25 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। जेएलएन चिकित्सालय से 35, सैटेलाइट चिकित्सालय से 5 तथा पंचशील अरबन सीएचसी से 10 मरीज डिस्चार्ज हुए। इससे पहले यह हालात थे कि हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों को जगह ही नहीं मिल पा रही थी।

होम डिलीवरी करेंगे दुकानदार

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और बाजारों में भीड़ रोकने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों के व्यापारियों ने शटर बंद रख कर सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही बिक्री करने का निर्णय किया है। जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों की बैठक में इस पर साझा समझ और सहमति कायम हुई। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिला प्रशासन और शहर के महत्वपूर्ण बाजारों के व्यापारियों की बैठक में यह निर्णय हुआ। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर गजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण के समय में बाजारों में भीड़ को कम करने तथा आमजन की सुरक्षा के लिए व्यापारियों व उनकी एसोसिएशन ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि शहर के पड़ाव, अनाज मंडी, केसरगंज, सीताराम बाजार, मदनगोपाल मार्ग, संजय मार्केट, डिग्गी बाजार, एवं अन्य बाजार किराणा मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। दुकानदार फोन या ऑनलाइन डिमांड पर अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी करेंगे। प्रशासन की ओर से इन दुकानों के डिलीवरी बॉय को आवागमन के लिए पास दिए जाएंगे।

राजस्थान में दो दिन में 16 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद, दो गिरफ्तार

जयपुर । राजस्थान में नशीली दवाओं का कारोबार काफी फैल रहा है। दो दिन में दो बड़े शहरों जयपुर व अजमेर से 16 करोड़ मूल्य की नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। सोमवार को अजमेर 11 करोड़ रुपये की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी गई। यहां पुलिस ने 114 कॉर्टन में तीन कंपनियों की नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अजमेर के रामगंज थाना इलाके में नशीली दवाइयों की खेप बरामद कर मोबिन व कालू नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर में नशे का कारोबार करने वाला मास्टरमाइंड राहुल चौहान फिलहाल फरार है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जिस गोदाम में नशे की खेप रखी हुई थी, उसका मालिक लतीफ भी फरार है। इससे एक दिन पहले रविवार को जयपुर में दो स्थानों पर कार्रवाई कर नशे की 25 लाख गोलियां बरामद की थी। इनकी कीमत पांच करोड़ रुपये बताई जा रही थी।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पहली कार्रवाई विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में की गई। यहां नाकेबंदी कर के एक टैंपो चालक मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार किया गया। उसके टैंपों से 25 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई। मोहम्मद ताहिर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह टैंपों में रखी टेबलेट न्यू सांगानेर रोड़ स्थित एक गोदाम से लेकर आया है। ये टेबलेट विश्वकर्मा इंडस्ट्रिय एरिया स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में छोड़ना है।

जहां से अजमेर जाएगी। इस पर पुलिस ने टैंपों में रखी टेबलेट बरामद की और सरगना को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन वह फरार हो गया। डीसीपी ने बताया कि जब्त की गई टेबलेट का वजन आठ क्विंटल से ज्यादा है। दूसरी कार्रवाई मुहाना इलाके में कार चालक राहुल जांगीड़ को गिरफ्तार कर के की गई। उसकी कार में प्रतिबंधित दवाओं का एक डिब्बा रखा हुआ था।

आसाराम का स्वास्थ्य फिर बिगड़ा, जेल में ही दी जा रही ऑक्सीजन

जोधपुर । कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। जेल से उसे एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर को बुलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अब जेल में उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। रविवार को उनका ऑक्सीजन लेवल 91-92 पर था, जिसके उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अभी दो दिन पूर्व ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के साथ आइसोलेशन पीरियड कम्प्लीट होने पर उनको एम्स से डिस्चार्ज किया गया था।

जोधपुर जेल में बंद आसाराम का रविवार से ऑक्सीजन लेवल घटकर 92 हो गया। इसके बाद जेल में ही उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। जेल अधिकारियों ने उसे पुनः एम्स ले जाने की बात कही, लेकिन आसाराम ने सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज लेने की बात कहते हुए एम्स जाने से मना कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन ने करवड़ की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डॉ अरुण त्यागी को बुलाया। उन्होंने आसाराम की जांच करके कुछ दवाइयां दीं। फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है।

डॉ त्यागी ने बताया कि कोविड के कारण आसाराम को कुछ दिक्कतें हैं। इलाज के लिए कुछ जांचें जरूरी हैं। ये जांचें अस्पताल में ही हो सकती है, इसलिए उनको अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। इसके बाद ही आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया जा सकता है। चिकित्सको के अनुसार उसे प्रोस्टेट की समस्या पहले थी जो अब और बढ़ गई है।

हाल ही में आसाराम ने इलाज के राजस्थान हाईकोर्ट में 2 महीने की अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी।हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इस कारण छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

अजमेर में गोदाम से सवा पांच करोड़ की नशीली दवाइयां और इंजेक्शन जब्त

अजमेर । राजस्थान में अजमेर पुलिस ने ब्यावर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम से करीब सवा पांच करोड़ रुपये की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए हैं। यह बरामदगी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सूचना पर की गई। 23 मई को ही जयपुर में ऐसी ही दवाइयों और इंजेक्शन जब्त किए गए थे। इनकी कीमत भी करीब पांच करोड़ रुपये आंकी गई। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र शर्मा ने बताया कि रामगंज पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम पर छापामार कर 114 कार्टून जब्त किए। इन कार्टून में नशीली दवाइया ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 100 एमजी, ट्रामाडोल इंजेक्शन 50 एमजी, ट्रामाडोल कैप्सूल 50 एमजी, ट्रामाडोल टैबलेट 50 एमजी की जब्त की गई। इसी प्रकार अल्प्राजोलाम 1एमजी की टेबल भी जब्त की गई। इन सभी टेबलेट और इंजेक्शनों की कीमत करीब सवा पांच करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके लिए अजमेर के सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह यादव का सहयोग भी लिया गया।

एसपी शर्मा ने बताया कि जब्त सभी दवाइयों प्रतिबंधित हैं और एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आती हैं। प्राथमिक जांच में अभी तक भी इन दवाइयों की बिलिंग कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने मौके से गोदाम के केयरटेकर मोबिन और कालू नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि मास्टर माइंड राहुल चैहान और गोदाम मालिक लतीफ की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि राहुल चैहान ने ही गोदाम को तीन हजार रुपये मासिक किराये पर ले रखा है। एसपी शर्मा ने माना कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों के स्टॉक के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय हैं।

यही वजह है कि इस गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा। नशीली दवाइयों का कारोबार समाज के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए सरकार ने ऐसे दवाइयों को एनडीपीएस एक्ट के दायरे में रखा है। उन्होंने बताया कि ऐसे अनेक दवाएं जब्त की गई है, जिनकी बिक्री का विवरण मेडिकल स्टोर वालों को रखना होता है, लेकिन अभी इन दवाओं की खरीद के स्थान की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विमला मार्केट में पूछताछ

अजमेर के स्टेशन रोड स्थित विमला मार्केट में दवाइयों का थोक कारोबार होता है। इस मार्केट में बड़ी कंपनियों के थोक विक्रेता अपना गोदाम और ऑफिस संचालित करते हैं। नशीली दवाइयों की जब्ती के बाद पुलिस ने विमला मार्केट के कुछ विक्रेताओं से भी पूछताछ की है। हालांकि जिन कंपनियों की दवाइयां जब्त की गई है, वे कोई नामी कंपनियां नहीं हैं। असल में ऐसे कंपनियों के द्वारा तैयार नशीली दवाइयों का उपयोग ही युवा वर्ग करता है। पिछले दिनों अजमेर के पुष्कर में भी नशीली दवाइयों के इंजेक्शन जब्त किए गए थे। जानकारों की मानें तो नशीली दवाइयों के कारोबार का अजमेर ट्रांजिक्ट पॉइंट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट नगर शहर से बाहर ब्यावर रोड पर बना हुआ है। चूंकि अभी ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनियों के दफ्तर पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुए हैं, इसलिए यहां आमतौर पर सूना पन बना रहता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर ड्रग्स के कारोबारियों ने यहां गोदाम बनाया है। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि इस गोदाम से कब से नशीली दवाइयों का कारोबार हो रहा था।

मुनमुन दत्ता के खिलाफ अहमदाबाद में एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज

अहमदाबाद । तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता के खिलाफ अहमदाबाद में एक समुदाय के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर जाति सूचक शब्द बोलने को लेकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई है। खोखरा पुलिस थाना इलाके की सहदेव सोसायटी में रहने वाले 64 वर्षीय वकील मधुभाई परमार ने अपनी शिकायत में बताया कि गत 11 मई को उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो देखा, जिसमें मुनमुन दत्ता एक जाति के बारे में टिप्पणी करती नजर आई। मुनमुन दत्ता ने जान-बूझकर अनुसूचित जाति के लोगों की भावना को दुखाया है। खोखरा पुलिस ने उनकी शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

गौरतलब है कि टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुनमुन के खिलाफ हरियाणा के हांसी में एफआइआर दर्ज हुई है। ये एफआइआर हाल ही में मुनमुन द्वारा एक वीडियो में जाति विशेष के बारे में टिप्पणी करने के चलते दर्ज हुई है। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत

कलसन की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कलसन ने 11 मई को दत्ता के खिलाफ हांसी पुलिस को एक शिकायत दी थी और वीडियो के साथ एक कॉम्पैक्ट डिस्क भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दत्ता ने एक मेकअप वीडियो में कहा कि वह अच्छी दिखना चाहती थीं और एक विशेष अनुसूचित जाति का उल्लेख करते हुए कहा कि वह उनकी तरह नहीं दिखना चाहती थीं।

ये है मामला- दरअसल, कुछ वक्त पहले मुनमुन ने एक वीडियो में जाति विशेष के बारे में टिप्पणी की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वो वीडियो वायरल हो गया और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्ट्रेस के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

मामले के तूल पकड़े ही मुनमुन ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। मुनमुन ने एक नोट में लिखा था, यह एक वीडियो के संदर्भ में है जिसे मैंने कल पोस्ट किया था। जहां मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए एक शब्द का गलत अर्थ लगाया गया है। यह अपमान, धमकी, या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से कभी नहीं कहा गया था। भाषा की सीमित जानकारी के कारण, मुझे उस शब्द के अर्थ के बारे में गलत जानकारी थी। अपने पोस्ट में मुनमुन ने आगे लिखा था, एक बार जब मुझे इसके अर्थ से अवगत कराया गया तो मैंने तुरंत उस भाग को निकाल दिया। मेरा हर जाति, पंथ या लिंग से हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत सम्मान है और हमारे समाज या राष्ट्र में उनके अपार योगदान को मैं स्वीकार करती हूं। मैं ईमानदारी से हर एक व्यक्ति से माफी मांगना चाहती हूं जो शब्द के उपयोग से अनजाने में आहत हुए हैं और मुझे उस के लिए खेद है।

वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में यह किरदार निभाएंगी समांथा अक्किनेनी

मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' को लेकर दर्शक और फिल्म समीक्षक काफी उत्साहित हैं। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। यह वेब सीरीज 4 जून 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। इस वेब सीरीज से साउथ एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। ट्रेलर देखने से मालूम पड़ रहा है कि सामंथा सीरीज में नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं जो की मनोज वाजपेयी की खिलाफ होगा। बताया जा रहा है कि समांथा इस सीरीज में एक आत्मघाती हमलावर की भूमिका में नजर आने वाली हैं। खबरों के मुताबिक, 'द फैमिली मैन 2' में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक पात्र समांथा का है। वह इस सीरीज में एक आत्मघाती हमलावर की भूमिका में दिखेंगी। सीरीज में वह एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई नजर आएंगी। समांथा और मनोज के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक होगी। बताया जा रहा है कि सीरीज में फिल्माया गया आतंकवादी संगठन काल्पनिक होगा। सच्ची घटना और ऐसे किसी संगठन से इसका ताल्लुक नहीं होगा। मेकर्स ने किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है। समांथा दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में करीब 11 सालों तक काम किया है। 'द फैमिली मैन 2' समांथा की पहली वेब सीरीज और हिन्दी का प्रोजेक्ट होगा। 'द फैमिली मैन' राज एंड डीके के निर्देशन में बनी है, जो थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जासूसी पर आधारित इस सीरीज में मनोज के साथ समांथा की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। प्रियामणि, शारिब, शरद केलकर और दर्शन इस सीरीज में वापसी करेंगे। वहीं, सनी हिंदुजा, श्रेया धनवंतरी, शहाब अली, वेदांत सिन्हा, महेक ठाकुर और सीमा बिस्वास भी दूसरे सीजन में दिखने वाले हैं।

वीडियो लीक होने पर राधिका आप्टे का छलका दर्द

राधिका आप्टे बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्रियों में से हैं। अपने अब तक के करियर में उन्होंने कई यादगार रोल किए। इन सबके बीच राधिका विवादों से भी घिरीं जब उनका न्यूड वीडियो लीक हो गया था। राधिका आप्टे को उस वक्त काफी ट्रोल किया गया था। अपने हालिया इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा कि इससे उन पर काफी बुरा असर पड़ा था।

जब लीक हुआ था न्यूड वीडियो

राधिका ने बताया कि उनका जो वीडियो लीक हुआ था उनके ड्राइवर से लेकर वॉचमैन तक उन्हें उसमें पहचान गए थे। ग्रैजिया मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राधिका ने कहा कि 'जब क्लीन शेव की शूटिंग के दौरान की एक न्यूड क्लिप लीक हुई तो मुझे बुरी तरह ट्रोल किया गया और इसने मुझ पर असर डाला। मैं चार दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकी इसलिए नहीं कि मीडिया में क्या कहा जा रहा था बल्कि मेरे ड्राइवर, वॉचमैन और मेरे स्टाइलिस्ट के ड्राइवर ने मुझे तस्वीरों में पहचान लिया था।'

यह सब सोचना समय की बर्बादी

राधिका आगे कहती हैं कि 'इसे अनदेखा करें। और कुछ भी आपके समय की बर्बादी है। इसलिए जब मैंने ब्लपार्च्डङ्क के लिए कपड़े उतारे तो मुझे एहसास हुआ कि छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है।'

न्यूड सीन देना आसान नहीं

फिल्म पार्च्ड में न्यूड सीन देने के सवाल पर राधिका कहती हैं कि 'यह आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त मैं अपनी बॉडी इमेज से जूझ रही थी। स्क्रीन पर न्यूड होना थोड़ा डराने वाला था। अब मैं इसे कहीं भी कर सकती हूं।' वो आगे कहती हैं कि 'बेशक फिल्म कई जगह गई और मेरे काम को सराहा गया।। मुझे सच में इस तरह के काम की जरूरत थी क्योंकि जब आप बॉलीवुड होते हैं तो आपको लगातार सलाह दी जाती है कि आपके शरीर के साथ क्या करना है। मैंने हमेशा सोच रखा था कि मैं अपने शरीर या चेहरे पर कभी कुछ नहीं करूंगी।' वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका आप्टे की फिल्म 'ओके कम्प्यूटर' हाल ही में रिलीज हुई।

कंगना ने की सामंथा अक्किनेनी की तारीफ

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर देखने के बाद दक्षिण की अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी की तारीफ की है। इस सीरीज का पहला ट्रेलर बुधवार सुबह ऑनलाइन जारी किया गया था। इस ट्रेलर में सामंथा का धांसू एंट्री दिखाया गया है। इस वेब शो के साथ सामंथा पहली बार हिंदी दर्शकों को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस ट्रेलर का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पोस्ट में लिखा, ''इस लड़की के पास मेरा दिल है।''

पहले भी तारीफ कर चुकी हैं कंगना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंगना को किसी की तारीफ करते हुए कम ही देखा गया है। लेकिन वह आए दिन सामंथा तारीफ करती रहती हैं। इससे पहले भी कंगना ने सामंथा की प्रशंसा करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया था।

इंप्रेसीव है सामंथा का लुक

अब ट्रेलर में सामंथा के लुक और एक्शन की बात करें तो वाकई में उन्होंने अपने धांसू एंट्री से सभी के दिल पर छा गई हैं। इस वेब शो में सामंथा एक खूंखार आतंकवादी के किरदार में नजर आने वाली हैं। जासूसी पर आधारित इस सीरीज में मनोज वाजपेयी के साथ समांथा की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। समांथा दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में करीब 11 सालों तक काम किया है। 'द फैमिली मैन 2' समांथा की पहली वेब सीरीज और हिन्दी का प्रोजेक्ट है।

अगर कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो मैं अगली के लिए तैयार हो जाती हूं

अभिनेत्री अमायरा दस्तूर का कहना है कि वह अपने करियर में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं, जहां फिल्म के खराब प्रदर्शन से वह प्रभावित नहीं होती हैं। उन्होंने बताया कि ''मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त फिल्में हैं जो अच्छा नहीं करती और अच्छा करती हैं और फिर में महसूस करती हैं कि यह नौकरी का हिस्सा है। एक फिल्म काम करती है और एक नहीं। मैं बस हंसती हूं और अगली फिल्म के लिए तैयार हो जाती हूं। जब तक मुझे काम मिलता है, मैं खुश हूं। जिस दिन नहीं, उसी दिन मुझे चिंता होगी।'' अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। वह कहती हैं ''दिन के आखिर में, मुझे लगता है कि मैं अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाई हूं जहां मैं रहना चाहती थी।'' उन्होंने आगे कहा ''मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं किसी को जाने बिना कितनी दूर आ गई हूं। मुझे कड़ी मेहनत पर विश्वास है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होगी कि मेरा करियर कहां जा रहा है। उम्मीद है, कि मेरा करियर अलग-अलग भूमिकाओं के साथ लंबी दूरी तय करेगा।'' एक तरफ उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो वहीं बॉलीवुड हमेशा उनके लिए खास रहा है। वह कहती है ''बॉलीवुड हमेशा मेरे लिए नंबर एक पर रहेगा। यह घर है। हिंदी सिनेमा तो मेरी खून में है (हिंदी सिनेमा मेरे खून में चलता है), लेकिन मुझे तमिल और अन्य उद्योगों में काम करना अच्छा लगता है। लेकिन दिन खत्म होने के बाद, घर घर है।'' बॉलीवुड के अलावा अमायरा मार्शल आर्ट के सुपरस्टार जैकी चैन के साथ फिल्म 'कुंग फू योगा' में काम कर चुकी हैं।

रवि दुबे हुए कोरोना निगेटिव

टेलीविजन अभिनेता और निर्माता रवि दुबे की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है। रवि ने गुरुवार को प्रशंसकों और अनुयायियों के साथ सोशल मीडिया पर ये खबर शेयर की। रवि ने विजय चिन्ह दिखाते हुए एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा ''हो गए जी निगेटिव।' 'इस महीने की शुरूआत में, रवि ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर बताया था कि वह वायरस से संक्रमित हो गए है। उन्होंने लिखा था, ''नमस्ते दोस्तों, अभी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों में जो कोई भी मेरे निकट संपर्क में आया है, उसे सलाह दूंगा कि वह अपना ख्याल रखें और अपने लक्षणों की निगरानी करें। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं अपने नजदीकी लोगों की भी देखभाल कर रहा हूं। सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें (जैसा कि आशावादी रहें)। भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें।'' वर्क फ्रंट की बात करें तो रवि और उनकी पत्नी, अभिनेत्री सरगुन मेहता, डेली सोप 'उड़ियां' के निर्माता हैं, जो इस साल की शुरूआत में प्रसारित होना शुरू हुआ। यह शो पंजाबी फिल्म 'सुर्खी बिंदी' से प्रेरित है और इसमें ईशा मालवीय, प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता मुख्य भूमिका में हैं।

सचल त्यागी 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' में अपने किरदार से मेल नहीं खाते

अभिनेता सचल त्यागी ने कहा कि टीवी शो 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' में उनके दुष्ट किरदार से उनका किसी भी तरह का कोई मेल नहीं हैं, लेकिन फिर भी भूमिका में कुछ बारीकियां जोड़ने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने शक्ति में कुछ बारीकियां जोड़ी हैं। वह असभ्य और दुष्ट है। वह प्रतिज्ञा से नफरत करता है। मैं इस चरित्र से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हूं। मैं पूरी तरह से अलग इंसान हूं।'' वे कहते हैं, ''प्रतिक्रिया अच्छी रही है, मैं वास्तव में खुश हूं कि लोगों ने मुझे शक्ति ठाकुर के रूप में स्वीकार किया है।'' सचल, जो वर्तमान में शो की शूटिंग कर रहे हैं, ने महामारी के बीच काम करने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि ''सभी सावधानियां बरती जा रही हैं, हर कोई मानदंडों का पालन कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम सही खाएं, आराम करें और अपने इम्यूनिटी के स्तर को ऊंचा रखें। हमें चलते रहना है। मैं बस कामना और प्रार्थना करता हूं कि यह तबाही खत्म हो जाए।'' अभिनेता ने 'घर एक सपना', 'अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो' और 'माता की चौकी' जैसे शो भी किए हैं।

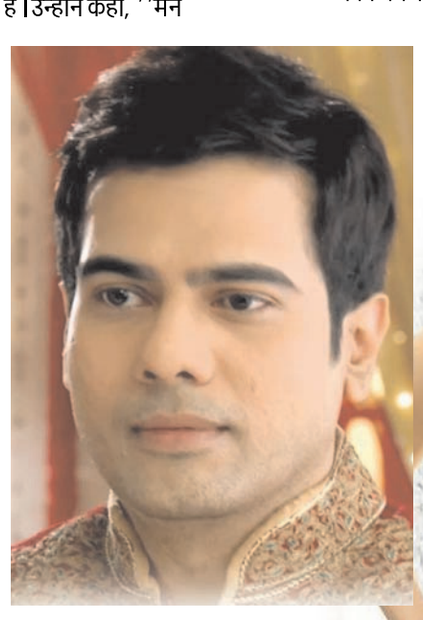

'खतरों के खिलाड़ी' का मिला ऑफर इस वजह से नहीं जाना चाहती

राखी सावंत पैपराजी की फेवरेट हैं। उन्हें कहीं ना कहीं स्पॉट कर ही लिया जाता है। राखी ने 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लिया था जिसके बाद शो की टीआरपी में जबरदस्त उछाल आया था अब बताया जा रहा है कि 'खतरों के खिलाड़ी 11' के लिए भी राखी को अप्रोच किया गया है। इसका खुलासा खुद उन्होंने ही किया है।

राखी ने किया दावा

फोटो जर्नलिस्ट वीरल भयानी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें राखी ने बताया कि 'खतरों के खिलाड़ी 11' अभिनव शुक्ला या फिर अर्जुन बिजलानी जीत सकते हैं। राखी कहती हैं कि 'खतरों के खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड का ऑफर आया है मुझे, अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता है कि मैं जाऊंगी या नहीं। वैसे ये सांप, बिच्छू, अजगर, ये कीड़े-मकोड़े मेरे बाएं हाथ का खेल है।'

रूबीना की वजह से नहीं जाना चाहती

राखी आगे कहती हैं कि 'अभी तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी, देखते हैं। अभी तो सभी दिग्गज हैं वहां पर, राहुल वैद्य गया है, अभिनव शुक्ला गया है। नहीं बाबा, मैं नहीं जाना चाहती वहां पर, रूबी (रूबीना दिलैक) नहीं है ना? क्या पता मेरा फिर से मेरा अफेयर हो जाए। हां लेकिन एक कबाब में हड्डी है वहां पर, तंबोली (निक्की तंबोली)। जब फोटोग्राफर्स ने उनसे पूछा कि निक्की तंबोली कबाब की हड्डी क्यों हैं तो राखी कहती हैं कि 'निक्की की भी तो आंख है अभिनव पर पहले से, मुझे पता नहीं है क्या? अभिनव बहुत चार्मिंग, डिसेंट है। एक और है अर्जुन बिजलानी। इन दोनों में से ही कौन जीतेगा।'

कौन जीतेगा 'खतरों के खिलाड़ी'?

राहुल वैद्य के जीतने की संभावना पर राखी कहती हैं कि 'वो चार-पांच हफ्ते ही रह पाएगा। उसकी मेडिकल कंडीशन मुझे पता है। वह बहुत अच्छा एंटरटेनर है लेकिन शो अर्जुन बिजलानी या अभिनव कोहली में से कोई जीतेगा। वो (अभिनव) शादीशुदा है। शादीशुदा मर्दों पर नजर नहीं डालते। मुझे पाप नहीं करना।'

पृथ्वी शॉ ने अपने मुश्किल दौर को लेकर किया अहम खुलासा, बताया 8 महीने के बैन के लिए कौन जिम्मेदार

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने साल 2019 में अपने ऊपर लगे बैन को लेकर अहम खुलासा किया है। शॉ का कहना है कि बैन के लिए वह और उनके पिता जी जिम्मेदार हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने शॉ को 8 महीने के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से प्रतिबंधित कर दिया था। शॉ ने एक ऐसा कफ सिरप ले लिया था, जिसमें 'टर्बुटलाइन' नामक प्रतिबंधित दवा शामिल थी। शॉ का यूरीन सैंपल लिया गया था, जिसके बाद उन्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था।

'उस समय मुझे सर्दी और खांसी थी'

पृथ्वी शॉ ने क्रिकबज से कहा, मुझे लगता है कि कफ सिरप विवाद के लिए पिता जी और मैं जिम्मेदार हैं। मुझे याद है कि हम इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे और उस समय मुझे सर्दी और खांसी थी। मैं रात के खाने के लिए बाहर गया था और काफी खांस रहा था। ऐसे में मैंने अपने पिता जी से बात की और उन्होंने मुझे मार्केट में उपलब्ध कफ सिरप लेने की सलाह दी। लेकिन मैंने जो गलती, वो यह कि फिजियो से परामर्श नहीं किया। मेरी तरफ से यह गलत थी।

'मैं हर जगह अपने बारे में पढ़ रहा था'

शॉ ने आगे कहा, मैंने उस सिरप को दो दिनों तक पिया और फिर तीसरे दिन मेरा डोप टेस्ट हो गया। टेस्ट में मुझे प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने लिए पॉजिटिव पाया गया। यह मेरे लिए बहुत कठिन समय था, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं हर जगह अपने बारे में पढ़ रहा था। मुझे लोगों की धारणा के बारे में चिंता थी। मुझे लगा कि लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रतिबंधित पदार्थ और ड्रग्स ले रहा हूं। मैं हर दिन इस विवाद बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर अचानक सबकुछ बदल गया।

भारतीय महिला क्रिकेटर्स के लिए ईसा गुहा ने उठाई आवाज, बोलीं- सिर्फ इस कदम से मिला सकता है हक

लंदन। इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर ईसा गुहा भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए एक प्लेअर्स एसोसिशन (खिलाड़ी संघ) चाहती हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश अखबार ने खबर दी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए उन्हें पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीयटीम फाइनल में पहुंची थी।

गुहा ने अपनी टाइमलाइन पर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट को कोट-ट्वीट करते हुए लिखा कि महिलाओं को प्रगति के लिए आभारी महसूस करने के लिए बनाया गया है लेकिन उन्हें बराबरी का हक देने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। खिलाड़ी संघ के माध्यम से भारतीय महिलाओं को यह हक मिल सकता है। द टेलीग्राफ में इंग्लैंड की पूर्व महिला अंतरराष्ट्रीय और खेल लेखक इसाबेल वेस्टबरी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 8 मार्च को समाप्त हुए 2020 टी20 विश्व कप के लिए मिली पुरस्कार राशि अब तक भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दी है। वेस्टबरी भारतीय बोर्ड पर अपने हमले में और भी अधिक तीखी थी, जब भारत के एक मीडिया आउटलेट में बीसीसीआई के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वह भुगतान करने में असमर्थ थाक्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से पुरस्कार राशि देर से मिली थी। वेस्टबरी ने बीसीसीआई के इस दावे को कवर-अप कहा क्योंकि उनके मुताबिक आईसीसी ने बीसीसीआई को अप्रैल, 2020 तक पुरस्कार राशि दे दी थी।

एफ1: वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रां प्री जीती, सात बार के चैंपियन हैमिल्टन पर बनाई बढ़त

मोनाको । मैक्स वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रां प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में पहली बार फार्मूला वन चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान से शुरुआत करने वाले वेरस्टापेन शुरुआत से ही नियंत्रण में दिखे। इससे पहले पोल पोजीशन हासिल करने वाले चार्ल्स लेकलर्क तकनीकी समस्या के कारण रेस शुरू नहीं कर सके। रेड बुल के वेरस्टापेन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने सात बार के फार्मूला वन चैंपियन लुईस हैमिल्टन पर चार अंक की बढ़त बना ली है। वेरस्टापेन की सत्र की यह दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। मर्सीडीज के हैमिल्टन सातवें स्थान पर रहे। फेरारी के कार्लोस सेंज जूनियर ने दूसरा जबकि मैकलारेन के लेंडो नौरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया।

मैनचेस्टर सिटी ने जीत के साथ किया प्रीमियर लीग का अंत, 10 साल में पांचवीं बार खिताब पर जमाया कब्जा

न्यूयार्क। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के सीजन का अंत जीत के साथ किया है। पहले ही ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी सिटी ने अंतिम मैच में एवर्टन को 5-0 से करारी शिकस्त दी।

बता दें कि सिटी ने 10 साल में पांचवीं बार खिताब पर कब्जा जमाया है। इस जीत के साथ सिटी अंक तालिका में टॉप पर काबिज रही। उसने 38 मैचों में से 27 में जीत हासिल की। वहीं, क्लब को 6 में हारा का मुंह देखना पड़ा जबकि 5 ड्रॉ रहे। लीग में दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर युनाइटेड रहा। युनाइटेड को इस सीजन में 21 जीत अपने नाम की की और 6 में हार मिली।

मैच में शुरू से हावी रहा मैनचेस्टर सिटी

सत्र के आखिरी मैच में मैनचेस्टर सिटी शुरुआत से ही एवर्टन के खिलाफ हावी रहा। सिटी ने पहले हाफ के 11वें मिनट में ही विपक्षी टीम को छकाते हुए गोल दाग दिया था। पहला गोल केविन डि बून ने दिलाई। इसके बाद सिटी ने एवर्टन को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उसने पहले हाफ में 2-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरा गोल रहीम स्टर्लिंग ने किया। एवर्टन को 37वें मिनट में पेनाल्टी मिली थी लेकिन गोलकीपर एडर्सन ने नुकसान नहीं होने दिया। दूसरे हाफ में एवर्टन ने काफी कोशिश की, मगर सिटी ने मुकाबले पर अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। सिटी ने 3 और गोल दागे, जिसके साथ वह चैंपियन बन गए।

सर्गियो अगुएरो का सफर हुआ समाप्त

मैनचेस्टर सिटी द्वारा ईपीएल का अंतिम मैच खेलने के साथ स्ट्राइकर सर्गियो अगुएरो का क्लब के संग सफर समाप्त हो गया है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने 10 साल तक क्लब के साथ रहने के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया है। अगुएरो ने अपने आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे हाफ में दो गोल दागे, जिससे सिटी का पलड़ा और भारी हो गया। उन्होंने 71वें और 76वें मिनट गोल मारकर सत्र का समापन किया। अगुएरो ने क्लब के लिए कुल 184 गोल दागे।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा जिम्बाब्वे क्रिकेट

रेयान बर्ल ने टीम के लिए स्पॉन्सर्स का इंतजाम करने की गुहार लगाई; बोले- मैच के बाद गोंद से जूते चिपकाने पड़ते हैं

हरारे। जिम्बाब्वे टीम इन दिनों आर्थिक तंगी और गुटबाजी से जूझ रही है। जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिम्बाब्वे के एक बल्लेबाज ने फटे जूते की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नेशनल टीम को स्पॉन्सर करने की अपील की। जिसके बाद जूता बनाने वाली कंपनी ने आगे आकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं।

दरअसल जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज रेयान बर्ल ने देश के क्रिकेटरों की खस्ता हालत की ओर ध्यान खींचते हुए फटे हुए जूतों की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि हमें हर सीरीज के बाद जूते को गोंद से चिपकाना पड़ता है। हमारी राष्ट्रीय टीम को स्पॉन्सर की जरूरत है, ताकि हमें हर सीरीज के बाद जूते को चिपकाने की जरूरत न पड़े। उनकी इस अपील का असर हुआ और जूते बनाने वाली कंपनी उनकी मदद के लिए तैयार हो गई। कंपनी ने बर्ल की पोस्ट पर जवाब दिया है कि अब आप गोंद को अलग रख दें।

1992 में जिंबाब्वे क्रिकेट को मिली टेस्ट का दर्जा

जिंबाब्वे क्रिकेट बोर्ड को 1983 वर्ल्डकप से पहले अंतरराष्ट्रीय टीम का दर्जा मिला था। वहीं 1992 में टेस्ट का दर्जा मिला। लेकिन टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूझना पड़ रहा है। कभी इस देश ने क्रिकेट को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। जिनका नाम आज भी जेहन में है। प्लावर बंधुओं एंडी और ग्रांट, एलिस्टेयर कैंपबेल, डेव हॉटन, हीथ स्ट्रीक और नील जॉनसन जैसे खिलाड़ी इस देश के हैं। इन खिलाड़ियों ने जिंबाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए काफी सफलता हासिल की।

ओडिशा : सीएम पटनायक के निजी सचिव कार्तिकेयन पांडियन को मिला हॉकी का प्रतिष्ठित अवार्ड

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और आईएएस वी कार्तिकेयन पांडियन को एफआईएच प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार एफआईएच की 47वीं कांग्रेस के दौरान मिला। हॉकी इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

हॉकी के विकास और प्रमोशन में कार्तिकेयन का महत्वपूर्ण योगदान

दरअसल, ओडिशा में हॉकी के विकास और उसके प्रचार को लेकर पांडियन ने काफी काम किया। बता दें कि पांडियन ने राजधानी भुवनेश्वर में पुरुषों के हॉकी विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए एफआईएच ने पांडियन को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा।

ओडिशा ने किया चुनौती का सामना

बता दें कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन झारखंड के रांची में होने वाला था लेकिन अंत समय में झारखंड ने आयोजन से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद भुवनेश्वर को इस चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया। ओडिशा ने चुनौती का सामना किया और 90 दिनों के अंदर इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पूरे एशिया से 1300 से अधिक एथलीटों और अधिकारियों ने भाग लिया और पहली बार भारत पदक तालिका में शीर्ष राष्ट्र के रूप में उभरा। ओडिशा ने एक बड़ा जोखिम उठाया क्योंकि यह आयोजन जुलाई में बारिश के मौसम में होना था।

विराट से ज्यादा रूट को मिलती अधिक सैलरी

नई दिल्ली। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच कॉन्ट्रॉक्ट को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। बोर्ड श्रीलंकाई क्रिकेटर्स की सैलरी में कटौती करना चाहता है, लेकिन प्लेयर्स अड़ गए हैं। खिलाड़ियों ने खुलकर नाराजगी का इजाहर किया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ इनकार कर दिया है। श्रीलंकाई टीम फिलहाल बांग्लादेशी दौरे पर है, जिसके बाद कोई फैसला होने की उम्मीद है। ऐसे में श्रीलंका के अलावा अन्य क्रिकेटर्स की सैलरी की भी खूब चर्चा हो रही है। आइए आपको उन कप्तानों की सैलरी के बारे में बताते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं।

कोहली नहीं इस कप्तान की सैलरी ज्यादा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। हालांकि, बतौर कप्तान सैलरी के मामले में विराट कोहली नहीं बल्कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट टॉप पर हैं। रूट को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सालाना 8.97 करोड़ रुपए मिलते हैं, जोकि सबसे अधिक सैलरी है। वहीं, भारतीय कप्तान कोहली को हर साल 7 करोड़ रुपए की फीस मिलती है। वह भारत की तीनों फॉर्मेट की टीमों के कप्तान हैं। इन दोनों के बाद ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच और टिम पेन का नंबर आता है, जिन्हें 4.8-4.8 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिंच टी20 और वनडे टीम के कप्तान हैं जबकि पेन टेस्ट टीम की अगुवाई करते हैं।

फ्रेंच ओपन क्वालीफायर : नागल का सामना मारकोरा से, ओटे से भिड़ेंगे प्रजनेश

नई दिल्ली। भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल फ्रेंच ओपन क्वालीफायर में अपने से कम रैंकिंग वाले इटली के रॉबर्टो मारकोरा से भिड़ेंगे जबकि प्रजनेश गुणेश्वरन और रामकुमार रामनाथन की पहले दौर में राह आसान नहीं होगी। रविवार को क्वालीफायर टूर्नामेंट का ड्रॉ हुआ। 23 साल के नागल ने क्ले कोर्ट पर होने वाले इस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में अब तक जगह नहीं बनाई है और उन्हें दुनिया के 191वें नंबर के खिलाड़ी मारकोरा के खिलाफ अच्छी शुरुआत करनी होगी। इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में चुनौती पेश करने वाले झज्जर में जन्मे नागल दो चैलेंजर स्तर के टूर्नामेंट में खेलने के बाद यहां आए हैं। वह चैलेंजर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।

ओटे से भिड़ेंगे प्रजनेश

दुनिया के 149वें नंबर के बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रजनेश पहले दौर में 152वें नंबर के जर्मनी के आस्कर ओटे से भिड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पहले दौर में शिकस्त के बाद से प्रजनेश ने किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया है। वह 2019 में चारों मेजर टूर्नामेंट में खेले थे।

महिला एकल में अंकिता का सामना एरिना से

कई प्रयासों के बाद भी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में नाकाम रहे दुनिया के 215वें नंबर के

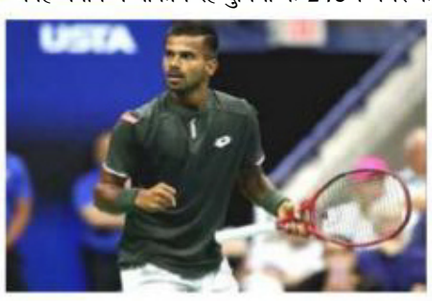

खिलाड़ी रामकुमार अपने अभियान की शुरुआत दुनिया के 168वें नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के माइकल ममोह के खिलाफ करेंगे। वहीं, महिला एकल में अंकिता रैना को पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की एरिना रोडियोनोवा से भिड़ना है।

दिहाड़ी मजदूरी को मजबूर हुई अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता, अब खेल मंत्रालय करेगा मदद

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन की मदद करेगा। इस बात की जानकारी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। रिजिजू ने कहा कि संगीता को उनका विभाग जल्द ही वित्तीय मदद मुहैया कराएगा।

रिजिजू ने ट्वीट किया, मुझे फुटबॉलर संगीता सोरेन के बारे में सूचित किया गया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस महामारी में वित्तीय संकट में हैं। मेरे कार्यालय ने उनसे संपर्क किया है और जल्द ही वित्तीय मदद दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। रिजिजू के कदम के बाद झारखंड सरकार भी इस खिलाड़ी की मदद के लिए आगे आई। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, संगीता सोरेन की हालत के बारे में कल संज्ञान लिया गया था। आज सुबह बाघमारा के बीडीओ (प्रखंड विकास अधिकारी) ने उनसे मुलाकात की और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता और राशन मुहैया कराया गया। कार्यालय ने कहा, उन्हें अपने खेल को जारी रखने के लिए जल्द ही राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। कार्यालय ने बताया, धनबाद के उपायुक्त आवासीय फुटबॉल केंद्र के कार्य को देखेंगे जहां संगीता को कोच/ प्रशिक्षक के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि महिला खिलाड़ियों को नियमित आय और प्रेरणा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया, हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री) के नेतृत्व में राज्य सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

एटलेटिको मैड्रिड 11वीं बार ला लीगा चैंपियन:वलाडोलिड को 2-1 से हराकर 7 साल बाद उठाई ट्रॉफी; जश्न मनाने के दौरान 14 साल के एक फैन की मौत

मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड ने 11वीं बार स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब जीत लिया है। उन्होंने हुए लीग के आखिरी दिन रियल वलाडोलिड को 2-1 से हराया। 2013/14 के बाद यह उनकी पहली ट्रॉफी रही। हालांकि, रियाल मैड्रिड भी विल्लारियल के खिलाफ अपना मुकाबला 2-1 से जीतने में कामयाब रही। ला लीगा में पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहने वाली टीम टाइटल अपने नाम करती है।

ऐसे में दूसरे नंबर पर मौजूद रियाल मैड्रिड को चाहिए था कि एटलेटिक अपना मैच हार जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। एटलेटिको के 38 मैच में 86 पॉइंट हैं। जबकि, रियाल के इतने ही मैच में 84 पॉइंट हैं। ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद एटलेटिको के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज रो पड़े। वहीं, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जश्न मनाने के दौरान एटलेटिको के 14 साल का एक फैन की मौत हो गई।वलाडोलिड ने पहले हाफ में बढ़त ली

वलाडोलिड ने पहले हाफ में ही बढ़त ले ली थी। मैच के 18वें मिनट में वलाडोलिड के ऑस्कर प्लानो ने गोल दागा। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 ही रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में एंजेल कोरिया ने 57वें और लुइस सुआरेज ने 67वें मिनट में गोल दाग टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। फुल टाइम तक एटलेटिको यह बढ़त बनाने में कामयाब रही।

मैच के बाद रोने लगे लुइस सुआरेज

एटलेटिको के लिए इस सीजन में सबसे कामयाब प्लेयर रहे सुआरेज मैच के बाद भावुक हो गए। उन्हें पिछले सीजन के बाद बार्सिलोना ने टीम से निकाल दिया था। सुआरेज के मुताबिक बार्सिलोना मैनेजमेंट ने उनसे कहा था कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं। वे अब हाई लेवल पर नहीं खेल सकते हैं। मुझे यह पसंद नहीं आया। मैं एटलेटिको का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मेरे लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखा। मैं यह चैंपियनशिप जीतकर बहुत खुश हूं।

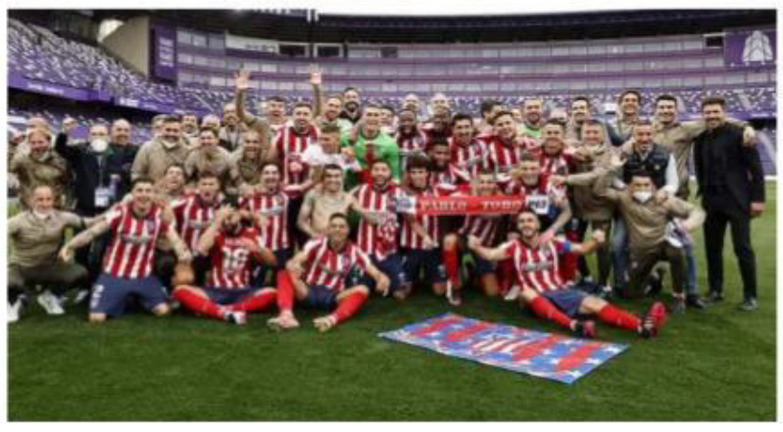

सुआरेज ने 32 मैच खेले और 21 गोल दागे

सुआरेज ने इस सीजन एटलेटिको के लिए ला लीगा में 32 मैच खेले और 21 गोल दागे। वहीं, 3 असिस्ट भी उनके नाम रही। 79त्न मैचों में वे एटलेटिको के स्टार्टिंग-11 में रहे। यह दूसरी बार है जब बार्सिलोना से निकलते ही अगले सीजन में उस खिलाड़ी ने एटलेटिको को चैंपियन बनाया हो। इससे पहले 2012 में डेविड विया को बार्सिलोना ने निकाल दिया था। वे एटलेटिको में गए और 2013 में टीम ने ला लीगा ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, इस बार सुआरेज के साथ ऐसा हुआ है।

एटलेटिको के कामयाब कोच बने डिएगो सिमोन

एटलेटिको मैड्रिड के कोच डिएगो सिमोन का यह पिछले 9 सीजन में दूसरा ला लीगा खिताब है। 2011 में उनके कोच बनने से पहले टीम ला लीगा पॉइंट्स टेबल में 9वें और 7वें नंबर पर रही थी। उनके कोच बनने के बाद 2 ट्रॉफी के साथ-साथ टीम कभी भी टॉप-3 से नीचे नहीं रही है।

मैड्रिड में हुआ हादसा, फैन की मौत

वहीं, मैड्रिड में जश्न मनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे एक 14 साल के फैन की मौत हो गई। मैड्रिड पुलिस के मुताबिक, वह चलती गाड़ी में से जैसे ही अपना सर बाहर निकाला, वह एक दीवार से टकरा गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है।